वर्ष: 3 अंक:18

16-31 मार्च, 2023 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

मध्यम वर्ग

नए भारत का सारथी

समृद्ध और विकसित नए भारत के सपनों को पूरा करने के लिए एक तिहाई आबादी वाला मध्यम वर्ग एक आधारस्तंभ है, जिनकी आकांक्षाओं को केंद्र सरकार ने बीते नौ वर्षों में दिए हैं नए पंख...

“दुनिया के कई देश भारत के UPI की ताकत की तरफ आकर्षित”

‘मन की बात’ कार्यक्रम को सभी लोगों ने जनभागीदारी की अभिव्यक्ति का एक अद्भुत मंच बना दिया है। हर महीने लाखों संदेश के जरिए कितने ही लोगों के ‘मन की बात’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है। जिस तरह मन की शक्ति बहुत अधिक होती है उसी तरह समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है यह ‘मन की बात’ कार्यक्रम के अलग-अलग एपिसोड में देखने और समझने को मिला है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी कहा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत के यूपीआई की ताकत सहित कई अन्य मुद्दों पर बात की। पेश है मन की बात के अंश...

- **भारतीय खिलौनों का क्रेज :** ‘मन की बात’ में जब भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे हाथों-हाथ बढ़ावा दिया। अब तो भारतीय खिलौनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। जब ‘मन की बात’ में हमने स्टोरी-टेलिंग की भारतीय विधाओं पर बात की तो इनकी प्रसिद्धि भी दूर-दूर तक पहुंच गई। लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्टोरी-टेलिंग की विधाओं की तरफ आकर्षित होने लगे।
- **भारत के UPI की ताकत :** भारत के UPI की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कई देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच UPI-Pay Now लिंक लॉन्च किया गया। भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ई-संजीवनी ऐप इसका जीता-जागता उदाहरण है। हमने देखा है कि कोरोना काल में इसके जरिए टेली-कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है।
- **उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार :** कुछ दिन पहले ‘उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार’ दिए गए। यह संगीत और परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में प्रतिभाशाली कलाकारों को दिए जाते हैं। यह कला और संगीत जगत की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ ही इसकी समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं।
- **स्वच्छ भारत में बड़ा योगदान :** हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम-से-कम प्लास्टिक के बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका यह संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा।
- **स्वच्छता भी, आमदनी का जरिया भी:** ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीज बनाती हैं। स्वच्छता के साथ ही यह आमदनी का भी जरिया बन रहा है।
- **कुंभ मेले का आयोजन :** पश्चिम बंगाल में त्रिबेनी को सदियों से एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। त्रिबेनी की विरासत को पुनर्स्थापित करने और कुंभ परंपरा के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए यहां पिछले साल कुंभ मेले का आयोजन किया गया था।

‘मन की बात’ पूरी सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

न्यू इंडिया
समाचार

वर्ष: 03, अंक: 18 | 16-31 मार्च, 2023

प्रधान संपादक
राजेश मल्होत्रा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

वरिष्ठ सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
जय प्रकाश गुप्ता (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)
पॉलमी रक्षित (बंगाली)

सीनियर डिजाइनर
राजीव भार्गव
डिजाइनर
अभय गुप्ता
फिरोज अहमद

अंदर के पन्नों पर
मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई उड़ान

आवरण कथा

बहुत तेजी से बदलते भारत में, विकास हो या व्यवस्था, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। | 10-26

'सम्मान' पाकर मेहनत करने की और मिलती है ताकत

वर्ष 2023 में घोषित पद्म सम्मान में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो इस बात के हैं जीवंत उदाहरण | 40-41

समाचार सार। | 4-5

व्यक्तित्व - कल्पना चावला
भारत में जन्म लेने वाली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला महिला सशक्तीकरण की एक ऐसी प्रतीक हैं जिन्होंने कल्पना से आगे की उड़ान भरी। | 6

विश्व मानवता को सुरक्षा का टीका
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च पर विशेष। | 7-9

सोच और अप्रोच बदल भारत ने दुनिया को दिखाया दम
ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में पीएम मोदी का संबोधन | 27-28

जूट की बोरियों में होगी अनाज की शत-प्रतिशत पैकिंग, 22वें विधि आयोग का बढ़ा कार्यकाल
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले | 29

करदाताओं की पाई-पाई का सही इस्तेमाल हो रहा सुनिश्चित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लिखित "सप्तऋषि" प्राथमिकताओं में से कई विषयों पर फरवरी के महीने में किया वेबिनार को संबोधित | 30-31

"कर्नाटक की प्रगति का मार्ग रेलवे, रोडवेज, वायुमार्ग और आई-वे की प्रगति से प्रशस्त"
पीएम मोदी कर्नाटक के लोगों से चार महीने में छठी बार हुए कनेक्ट, दी सौगातें | 32-33

जनजातीय उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव
आदि महोत्सव का नई दिल्ली में आयोजन | 34-35

भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवंतता विश्व के लिए प्रेरणा
जी-20 की बैठकों की जानकारी | 36-37

नए भारत में वैश्विक होती हिंदी
हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार के लिए 15 से 17 फरवरी तक फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का किया गया आयोजन | 38-39

मानवता के प्रति भारत के समर्पण और प्रतिबद्धता का दर्शन
मानवीय चेहरा बने तुर्किए-सीरिया से लौटे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संवाद | 42-44

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

'न्यू इंडिया समाचार' के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें:- @NISPIBIndia

आजादी के लिए समग्र भारत में जगाई चेतना की मशाल

भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने न सिर्फ आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी बल्कि जन-जन को जागृत करने का भी काम किया | 45-48

प्रकाशक और मुद्रक- मनीष देसाई , महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो **मुद्रण:** इनफिनिटी एडवर्टाइजिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, एफबीडी वन कॉर्पोरेट पार्क, 10वीं मंजिल, नई दिल्ली-फरीदाबाद बॉर्डर, एनएच-1, फरीदाबाद-121003। **पत्राचार और ईमेल के लिए पता:** कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली- 110003। **ईमेल-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

नियति नहीं, नीतियों से मिल रहे मध्यम वर्ग को नए अवसर

सादर नमस्कार।

केंद्र सरकार ने 'सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। जबकि एक समय था जब नए भारत की मुख्यधारा बने मध्यम वर्ग को नियति के भरोसे ही छोड़ दिया गया था। वह एक ऐसा युग हुआ करता था जब मध्यम वर्ग के मन में सुरक्षा की कोई भावना नहीं थी। चाहे आर्थिक हो या अन्य प्रकार की सुरक्षा लेकिन 2014 से केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है और उन्हें ऐसी सुरक्षा प्रदान की है कि आज परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है।

कुल मिलाकर देखें तो मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं से जुड़े हर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने लगातार राहत देने, मध्यम वर्गीय परिवार की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने का काम किया है। साथ ही खाने-पीने की चीजों से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक, लोन से लेकर आयकर तक सरकार ने हर प्रकार से जीवन को आसान बनाने का भी भरसक प्रयास किया है। देश में नए-नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन सुधारे जा रहे हैं, बड़े-बड़े शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, मोबाइल डाटा की कीमत कम हो रही है, इन सबका लाभ भी सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को ही मिलता है। हर मध्यम वर्गीय परिवार का अपने बच्चों के भविष्य के लिए भरोसा बना है कि अब उनके बच्चों का उज्ज्वल भविष्य निश्चित है।

मध्यम वर्ग को जब भी अवसर मिला है, उसने चमत्कार कर दिखाया है। इस वर्ष के गरीब और मध्यम वर्ग हितैषी आम बजट की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने बीते नौ वर्षों में किस तरह से मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है, यही इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है।

व्यक्तित्व की कड़ी में प्रेरणा की पंख बनीं कल्पना चावला, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर टीके के क्षेत्र में इंद्रधनुषी पहल, विश्व हिंदी सम्मेलन, तुर्किए-सीरिया की भूकंप में मानवता का दर्शन बने भारत की कहानी को विशेष रूप से इस अंक में रखा गया है। अमृत महोत्सव की श्रृंखला में गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा, जी-20 से जुड़े कार्यक्रम, पद्म पुरस्कार से सम्मानित नायकों की कहानी और पखवाड़े भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र को समर्पित परियोजनाओं और अन्य कार्यक्रमों को इस अंक में शामिल किया गया है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।

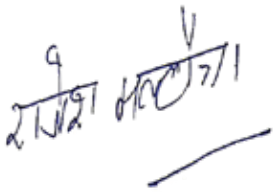

(राजेश मल्होत्रा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

क्रांतिकारियों की प्रेरक जीवनी करती हैं देशभक्ति के लिए प्रेरित

न्यू इंडिया समाचार का 16-28 फरवरी 2023 के नवीनतम अंक में अमृतकाल के पहले आम बजट पर कवर स्टोरी प्रकाशित की गई। यह हमें विकसित भारत के भव्य सपने को पूरा करने की मजबूत नींव के बारे में बताती है। इस अंक में आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित मौलाना अबुल कलाम आजाद, विजय सिंह पथिक, रफी अहमद किदवई, गणेश वासुदेव मावलंकर जैसे क्रांतिकारियों की प्रेरक जीवनी देशभक्ति के लिए प्रेरित करती हैं। यदि यह कहा जाए कि इन जैसी विभूतियों के कारण ही देश आजाद हुआ है तो गलत नहीं होगा। यह सभी विशेष सम्मान के हकदार हैं। भारत के ऐसे वीर सपूतों को शत-शत नमन।

b.balaji@midhani-india.in

इस पत्रिका में प्रकाशित की जाती है अच्छी जानकारी

मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023 का अंक प्राप्त हुआ। इस पत्रिका में संपादकीय बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही आवरण पृष्ठ भी सराहनीय होता है। समसामयिकी विषयों पर आपकी इस पत्रिका में अच्छी जानकारी प्रकाशित की जाती है।

shrigopal6@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का नियमित पाठक हूं

मैं न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का नियमित पाठक हूं। अत्यंत सुंदर कलेवर में यह पत्रिका गुणवत्ता पूर्वक प्रकाशित हो रही है। यह आनंद का विषय है। जैसा कि मुझे जानकारी है यह पत्रिका अभी 13 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। भारतीय भाषाओं का संवर्धन इस माध्यम से हो रहा है। इसी क्रम में संस्कृत भाषा में भी यह पत्रिका प्रकाशित हो ऐसा विनम्र निवेदन और आग्रह है।

गवीश द्विवेदी

skt.ststephens@gmail.com

अच्छी लगती हैं पत्रिका की सकारात्मक खबरें

मैं अमेरिका में रहने वाला एक एनआरआई हूं। मैं भारत और सरकार के काम का प्रशंसक हूं जो देश के नागरिकों की भलाई के लिए अथक प्रयास कर रही है। मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका में भारत में होने वाली सकारात्मक खबरें अच्छी लगती हैं। कृपया अच्छा काम जारी रखिए।

वेंकट

vabhagavatula@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका के कई लेख प्रेरणादायक

मुझे न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक पत्रिका पढ़ने को मिल रही है। पिछले पांच-छह अंक से मैं यह पत्रिका पढ़ रहा हूं जो मुझे अच्छी लग रही है। मुझे इसके कई लेख प्रेरणादायक और फिर से प्रकाशित करने लायक लगे। पत्रिका में सरकार की कई योजनाओं को और अधिक स्पष्ट रूप से बताया गया है। पत्रिका की जानकारी मैंने सोशल मीडिया पर और अपने मित्रों एवं परिवार के सदस्यों के साथ साझा की।

pm.maid@gmail.com

हमें फॉलो करें @NISPIBIndia

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली- 110003। ईमेल- response-nis@pib.gov.in

विकास के भारतीय मॉडल की दुनिया हो रही मुरीद

भारत की प्रगति के आयाम अब दुनिया के लिए आदर्श बन रहे हैं। दुनिया के कई देश भारत की योजनाओं का अध्ययन कर अपने यहां लागू कर रहे हैं। भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ हो, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, भारत की ओर से गरीबी कम करने के प्रयास, स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आईटी-इनोवेशन, यूपीआई आदि की प्रशंसा इन मंचों से अक्सर होती रही है।

विकास के भारतीय मॉडल को लेकर अब माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के

सह अध्यक्ष बिल गेट्स लिखते हैं, "कुल मिलाकर भारत मुझे भविष्य के लिए उम्मीद देता है। भारत ने साबित कर दिया है कि वह बड़ी चुनौतियों से निपट सकता है। देश ने पोलियो का उन्मूलन किया, एचआईवी ट्रांसमिशन को कम किया, गरीबी को कम किया, शिशु मृत्यु दर में कटौती की और स्वच्छता और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि की। भारत ने इनोवेशन के लिए एक वर्ल्ड लीडिंग अप्रोच को विकसित किया है जो यह सुनिश्चित करता है कि समाधान उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी आवश्यकता है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स के इन विचारों को अपने ट्वीटर पर साझा भी किया है।

3-8 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए लॉन्च हुआ 'जादुई पिटारा'

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में बढ़ते भारत ने बचपन से सीखने और सिखाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बच्चों में सीखने के परिदृश्य को और अधिक जीवंत बनाने के लिए 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल-आधारित शिक्षण-अध्यापन सामग्री 'जादुई पिटारा' लॉन्च किया गया है। प्लेबुक, खिलौने, पहेलियां, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कहानी की किताबें, वर्कशीट के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति, सामाजिक संदर्भ और भाषाओं को मिलाकर बना 'जादुई पिटारा' जिज्ञासा को बढ़ाने और लोगों की विविध आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

'जादुई पिटारा' 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इस पिटारे में केवल किताबें ही नहीं, बल्कि सीखने और सिखाने के लिए अनगिनत संसाधनों का उपयोग किया जाना है। यह सीखने-सिखाने के माहौल को समृद्ध करने और अमृत पीढ़ी के लिए इसे और अधिक बाल-केंद्रित, जीवंत और आनंदमय बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। इस नई पहल की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि खेलते हुए सीखने के क्षेत्र में यह बड़ी सफलता है क्योंकि जादुई पिटारा बच्चे के मन में एक नया जोश और रंग भरने वाला है।

खादी क्षेत्र के बुनकरों-कारीगरों-श्रमिकों की आय बढ़ेगी

कारीगरों की मासिक आय में 33% तो बुनकरों की मजदूरी में 10% की ऐतिहासिक वृद्धि

'खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन एंड खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूत्र वाक्य ने खादी का कायाकल्प कर दिया है। देश-दुनिया में भारतीय खादी के प्रति बढ़ते आकर्षण ने खादी को पुनर्जीवित किया है। खादी क्षेत्र के सूत कातने वाले तथा बुनकरों ने खादी का उत्पादन बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। ऐसे में खादी क्षेत्र से जुड़े बुनकर-कारीगरों को भी उसका स्वाभाविक लाभ देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने श्रमिकों की आय में बढ़ोतरी के लिए उनका मेहनताना 7.50 रुपये प्रति लच्छे से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लच्छा करने का निर्णय लिया है। इस पहल से कारीगरों की मासिक आय में लगभग 33% की वृद्धि होगी और बुनकरों की मजदूरी में 10% की वृद्धि होगी। यह निर्णय पहली अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा।

खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रम से जुड़े श्रमिकों के हाथों में अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराने, उनकी आय के स्रोत बढ़ाने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने का यह निर्णय एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। सनद रहे कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन 84,290 करोड़ रुपये और बिक्री 1,15,415 करोड़ रुपये की हुई थी। बीते 2 अक्टूबर को खादी इंडिया के कनॉट प्लेस बिक्री केंद्र ने एक ही दिन में 1.34 करोड़ रुपये के खादी उत्पाद बेचने का नया रिकॉर्ड बनाया था।

'ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन' सेवा ने हासिल किया 10 करोड़ परामर्श का लक्ष्य

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।। देशवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार की वरदान पहल 'ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन' सेवा ने 10 करोड़ परामर्श का लक्ष्य हासिल किया है। 'ई-संजीवनी' अपने नाम के अनुरूप ही मरीजों के लिए संजीवनी सिद्ध हो रही है।

भारत ने राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें केवल एक क्लिक पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। 10 करोड़ टेली-कंसल्टेशन के इस पड़ाव में 57 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं और 12 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक हैं। इस मंच ने आबादी के सबसे असुरक्षित वर्गों में पहुंच बनाकर प्रभाव दिखाया है। अब भारत सरकार 'ई-संजीवनी 2.0' शुरू कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे लोग डॉक्टरों की सलाह ले पा रहे हैं क्योंकि मौजूदा केंद्र सरकार भारत में एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य ई को-सिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि हर नागरिक रहे स्वस्थ और राष्ट्र हो सशक्त।

2024 तक 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करेगा भारत

ग्रामीण क्षेत्रों तक महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की केंद्र सरकार की पहल प्रभावी सिद्ध हो रही है। बीते 9 वर्षों के प्रयासों से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ने अपने कार्यों से सही मायने में खुद को राष्ट्र सहायता समूह के रूप में स्थापित किया है। 2014 में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या केवल 2.35 करोड़ थी लेकिन अब यह संख्या 9 करोड़ से अधिक हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप वर्ष 2024 तक इसके सदस्यों की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जिसके लिए मंत्रालय नई महिला सखियों को नामांकित करने के लिए सक्रिय मोड पर काम कर रहा है। उनका कहना था कि इन प्रयासों से कुछ वर्षों के भीतर केंद्र सरकार 10 लाख लखपति दीदियों के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगी और वह दिन दूर नहीं जब कुछ लखपति दीदियां करोड़पति दीदियां बन जाएंगी। स्वयं सहायता समूहों की उपस्थिति 97% प्रखंडों में है, जबकि उनमें से 85% सीधे मंत्रालय के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ●

कल्पना चावला
प्रेरणा की 'पंख'

जन्म: 17 मार्च 1962
मृत्यु: 1 फरवरी 2003

भारत में जन्म लेने वाली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला महिला सशक्तीकरण की एक ऐसी प्रतीक हैं जिन्होंने कल्पना से आगे की उड़ान भरी। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार अंतरिक्ष की यात्रा की और दिखाया कि भारत की बेटियों के लिए आसमान की ऊंचाई भी कम पड़ सकती है। विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरक इतिहास रचने वाली कल्पना चावला ने लोगों में अपने उत्साह और उमंग को बनाए रखने, बेटियों को आगे बढ़ने एवं अकल्पनीय ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। कोलंबिया अंतरिक्षयान दुर्घटना में भले ही वह हमें छोड़ कर चली गई लेकिन दुनिया भर में लाखों युवाओं के लिए आज भी बनी हैं मिसाल और प्रेरणा...

दुनिया से जाने के बाद भी जिन लोगों को प्रेरणा का स्रोत माना जाता है उसमें भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहीं कल्पना चावला का नाम भी शामिल है। पिता बनारसी लाल चावला और मां संज्योती के घर 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में जन्म लेने वाली कल्पना यहीं पली-बढ़ी। घर में सबसे छोटी कल्पना कम उम्र से ही विज्ञान में रुचि रखती थी। अंतरिक्ष, फ्लाइट के सपने देखने वाली कल्पना की इच्छा को देखते हुए पिता ने बात नहीं टाली। उच्च शिक्षा के लिए कल्पना चावला अमेरिका चली गईं। 1988 में वह अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा से जुड़ गईं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष सफर एसटीएस 87 कोलंबिया शटल के साथ 19 नवंबर 1997 को शुरू हुआ। इस उड़ान में कल्पना चावला ने करीब 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और धरती के 252 चक्कर लगाए यानि 65 लाख मील की दूरी तय की।

पहली सफल अंतरिक्ष यात्रा के करीब पांच वर्ष 10 महीने बाद नासा ने एक बार फिर कल्पना चावला को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया। 16 दिवसीय मिशन की सात सदस्यीय टीम में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया। भारत की बेटी कल्पना चावला ने 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष में दूसरी बार उड़ान भर भारत का नाम रौशन किया। हालांकि, यह उनकी अंतिम उड़ान साबित हुई क्योंकि कोलंबिया शटल अंतरिक्ष मिशन पूरा कर जब वापस लौट रहा था तब पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते समय 1 फरवरी 2003 को यह टूटकर बिखर गया। यान में सवार अन्य छह सदस्यों के साथ कल्पना चावला की भी मौत हो गई। कल्पना चावला भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन आज भी अंतरिक्ष की ओर देखती बेटी कल्पना चावला बन देश का नाम रौशन करना चाहती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तब उन्होंने 6 जून 2016 को अंतरिक्ष शटल यान कोलंबिया स्मारक पर कल्पना चावला को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2018 को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में कल्पना चावला को याद करते हुए कहा था, "यह सबके लिए दुःख की बात है कि हमने कल्पना चावला को इतनी कम उम्र में खो दिया लेकिन उन्होंने अपने जीवन से पूरे विश्व में खासकर भारत की हजारों लड़कियों को यह संदेश दिया कि नारी शक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है। इच्छा और दृढ़ संकल्प हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।" ●

राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस -16 मार्च

विश्व मानवता को सुरक्षा का टीका

वैज्ञानिक तरीके से बार-बार साबित हुआ है कि किसी भी बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका वैक्सीन है। कोविड महामारी के दौरान भी यह साबित हुआ कि कैसे वैक्सीन जिंदगी की डोर टूटने से रोकती है। भारत सरकार ने न सिर्फ देश बल्कि मानव जाति की चिंता की। यही कारण है कि वैक्सीन की हर खुराक के लिए जब विश्व समुदाय भारत की ओर देख रहा था तब अपनी जरुरतों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करीब 100 देशों को कोविड की गंभीरता से बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। भारत, विश्व में सभी तरह की 60 फीसदी वैक्सीन की मांग को पूरा कर रहा है, यह अपने आप में मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। 16 मार्च को जब देश राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मना रहा है तब स्वस्थ मानव समाज की सेवा पर राष्ट्र है गर्वित...

स्वस्थ जीवन और मृत्यु दर कम करने के लिए टीकाकरण एक बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली हथियार है। यही वजह है कि देश में विश्व का सबसे बड़ा और मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 12 तरह की जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए देश भर में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) चलाया जा रहा है जिसमें 11 तरह की वैक्सीन दी जा रही है। शिशु और गर्भवती के जीवन को संकट से बचाने के लिए डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन में होने वाली तपेदिक, हेपेटाइटिस-बी, मेनिन्जाइटिस, रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और देश में ऐसे जिले जहां जापानी बुखार के मामले हैं, वहां इस बीमारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था की गई है।

गर्भवती और नौनिहालों के बेहतर भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की जिसका असर यह हुआ कि जहां वर्ष-2014 में प्रति एक हजार जन्म लेने वाले बच्चों में से 45 की मौत हो जाती थी जो वर्ष 2020 में घटकर 32 रह गई। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ-साथ कई अन्य मंत्रालयों को यह जिम्मा दिया गया कि देश में गर्भवती माताओं और दो वर्ष तक की उम्र वाले सभी ऐसे बच्चे जिनका पूर्ण टीकाकरण नहीं हो

सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की यात्रा

देश में 16 जनवरी 2021 को कोविन एप के माध्यम से कोविड की गंभीरता से बचाव के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई और 21 अक्टूबर 2021 तक 100 करोड़ डोज लग चुके थे। 17 जुलाई 2022 को भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह सब रीयल टाइम में रिकार्ड भी होता गया। 17 जुलाई 2022 को 200 करोड़ डोज पूरे हुए। इसे संभव बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच का उपयोग किया गया। 2.64 लाख से अधिक टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और 4.76 लाख अन्य टीकाकरण दल के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

भारत में टीकाकरण की यात्रा

- वर्ष 1978: देश में टीकाकरण की शुरुआत हुई।
- यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी) की शुरुआत 1985 में हुई।
- 12 तरह की गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है।
- 27 मार्च 2014: भारत को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण मिला।
- 14 जुलाई 2016: डब्ल्यूएचओ से भारत को मातृ और नवजात टेटनस मुक्ति का प्रमाण मिला।
- मई 2019: वैक्सीन लगने के बाद होने वाले दुष्प्रभाव का सर्विलांस शुरू हुआ। विश्व की 60 फीसदी वैक्सीन की जरूरतों को भारत करता है पूरा।

28.14 करोड़ डोज:

वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने 99 से अधिक देशों और संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन पीसकीपर्स और यूएन हेल्थ वर्कर्स को दिया वैक्सीन।

दुनिया में सबसे आगे हम

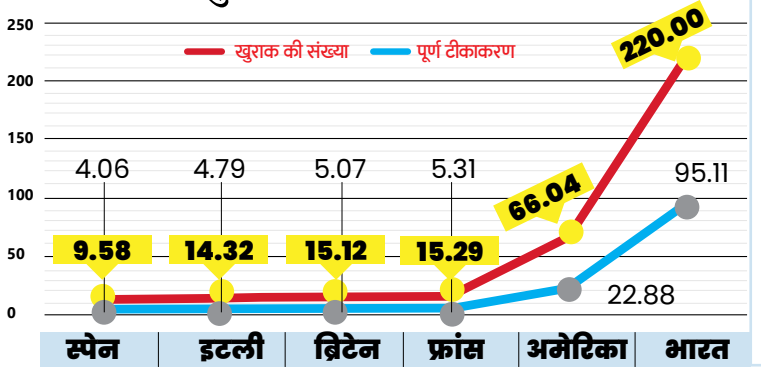

(नोट: खुराक और लाभार्थियों की संख्या करोड़ में, सभी आंकड़े 20 दिसंबर 2022 तक के हैं।)

दुनिया को दिखाया सामर्थ्य

- 40 करोड़ वैक्सीन खुराक देने में अमेरिका को जहां 298 दिन लगे वहीं भारत को इस आंकड़े तक पहुंचने में महज 183 दिन लगे।
- 92.21 करोड़ वयस्क आबादी को कम से कम एक डोज जरूर लगाई गई है। यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या का तीन गुना और रूस की जनसंख्या का सात गुना है।
- देश में 86.50 करोड़ वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हुआ है जो ब्राजील की जनसंख्या का 4.4 गुना और ब्रिटेन की जनसंख्या का 14 गुना है।

पाया है, उन तक पहुंचा जाए और कम से कम 90 फीसदी पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो। वर्ष-2017 में मिशन इंद्रधनुष की रफ्तार को और बढ़ाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि देश ने इसे मिशन मोड पर लिया और अभी तक मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत 4.45 करोड़ बच्चे और 1.12 करोड़ गर्भवती का पूर्ण टीकाकरण किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से चलाये गए इस अभियान के सफल परिणाम के बाद मीजल्स और रूबेला बीमारी से बचाने और इस बीमारी के खात्मे के लिए मीजल्स-रूबेला वैक्सीन को वर्ष 2017 में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया। इसे भी अभियान की तरह चलाया जा रहा

हमारे देश में पहले दूर-दराज के क्षेत्रों तक वैक्सीन पहुंचने में कई-कई दशक लग जाते थे। देश वैक्सीनेशन कवरेज के मामले में बहुत पीछे था। देश के करोड़ों बच्चों, खास कर गांवों और ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले बच्चों को वैक्सीन के लिए बरसों का इंतजार करना पड़ता था। अगर पुरानी अप्रोच के साथ काम करते तो भारत में वैक्सीनेशन कवरेज को शत-प्रतिशत करने में कई दशक और बीत जाते। हमने नई अप्रोच के साथ काम शुरू किया, मिशन इंद्रधनुष शुरू किया और पूरे देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था को सुधारा। जब कोरोना वैश्विक महामारी आई तो इस नई व्यवस्था, नए सिस्टम का लाभ दूर-सुदूर वैक्सीन पहुंचाने में मिला।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

है क्योंकि वर्ष 2023 में ही इसके खात्मे का लक्ष्य रखा गया है। न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाव के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन को भी 2017 में ही राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और उनके दिशा-निर्देश का ही असर है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 (2015-16) में जहां देश में टीकाकरण का प्रतिशत 62 फीसदी था वह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 (2019-21) में बढ़ कर 76.6 फीसदी तक पहुंच गया है।

यह सब संभव तभी हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में वैक्सीन की सुरक्षित पहुंच के साथ-साथ कोल्ड चेन प्वाइंट की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई। वैक्सीन की बर्बादी रोकने के साथ-साथ जिस सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है वहां समय पर वैक्सीन की पहुंच बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (ई-वीन) की शुरुआत हुई और इसका व्यापक तरीके से उपयोग किया गया। देश में 29,000 कोल्ड चेन प्वाइंट, 52,000 आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर और 46,000 डीप फ्रीजर का इस्तेमाल वैक्सीन स्टोर और वितरण के लिए किया जा रहा है।

देश में वर्ष 2014 के बाद टीकाकरण अभियान के लिए तकनीकी रूप से इतना व्यापक और मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया कि कोविड महामारी के दौरान बिना समय गंवाए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक कोविड वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित हो पाई। वैक्सीनेशन के लिए नदी पार करना हो, पहाड़ चढ़ना हो, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाना हो, राजस्थान के मरुस्थल तक पहुंचना हो या कठिन से कठिन इलाकों में ड्रोन या हेलीकॉप्टर से वैक्सीन या वैक्सीनेटर को पहुंचाना हो या डोर-टू-डोर कैंपेन के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हो, इसका अभ्यास भारत को इन आठ वर्षों में हो चुका था। इसी का नतीजा था कि भारत विश्व में सबसे जल्दी सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला देश बना। स्वास्थ्य और खास कर मिशन इंद्रधनुष अभियान के दौरान टीकाकरण के लिए तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का महामारी के दौरान बहुत लाभ मिला। ●

मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई उड़ान

बहुत तेजी से बदलते भारत में, विकास हो या व्यवस्था, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए एक तिहाई आबादी वाला मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है, जिनकी आकांक्षाओं को केंद्र सरकार की ओर से बीते नौ वर्षों में नए पंख मिले हैं। अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए ईज ऑफ लिविंग के साथ उसे विकास का सहभागी बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। अमृत काल के पहले आम बजट में भी मध्यम वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई है ताकि 'सबका प्रयास' की भावना से विकसित नए भारत का हो निर्माण...

आजादी के बाद से ही देश के विकास में भारत के मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग और अभूतपूर्व जनसांख्यिकीय लाभ के साथ विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अगर भारत को अगली पीढ़ी की अर्थव्यवस्था (नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमी) बनना है तो उसके लिए जरूरी शर्तों में एक यह भी है कि मध्यम वर्ग की आय और जीवन स्तर में और सुधार करना होगा। इस दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों को जानने से पहले यह भी समझना होगा कि 2014 से पहले इस वर्ग की स्थिति क्या थी?

दरअसल, पहले एक ऐसा युग हुआ करता था जब मध्यम वर्ग के मन में सुरक्षा की कोई भावना

> दरअसल यही नया भारत है, जिसका मतलब है युवा शक्ति के सपने का निर्माण करना, एक ऐसा भारत जो नारी शक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करता हो, जहां गरीबों के लिए आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर हो, गरीबों और मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं भारत को नई ऊंचाईयों पर ले जाए।
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

इस वर्ष के गरीब, मध्यम वर्ग हितैषी बजट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विकसित भारत के लिए सब जुड़ें-जुटें, सबका प्रयास कैसे हो, इसकी ताकत बजट देगा।

नहीं थी।चाहे आर्थिक हो या अन्य प्रकार की सुरक्षा लेकिन आज वह ऐसे दौर में हैं जहां उनके पास कई स्तरों पर लाभ उपलब्ध हैं।ऐसे में भारत का मध्यम वर्ग और उसकी आकांक्षा काफी हद तक सशक्त हुई है।अपने घर के सपने को साकार करने से लेकर आय बढ़ाने तक, सशक्त करने वाली नीतियों से लेकर असामाजिक तत्वों को सजा देकर सुरक्षा की भावना लाने तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फल-फूल रहा है।कई सरकारी पहल का मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।जिस मध्यम वर्ग के सामर्थ्य और क्षमता को अनदेखा किया जा रहा था, उसे पहली बार देश की राजनीति और शीर्ष नेतृत्वकर्ता ने नई पहचान दी है।गरीबी को खत्म कर मध्यम वर्ग पर लगातार लादे जा रहे बोझ को कम करने का उनका दृष्टिकोण व नीतियां भी व्यावहारिक हैं।एक संतुलित एवं आदर्श समाज निर्माण के लिए यह न केवल जरूरत है बल्कि समय की मांग भी है।लगातार इस वर्ग की उपेक्षा के छाए घनघोर बादल अब छंटते हुए दिखाई दे रहे हैं।इस आदर्श स्थिति की तरफ बढ़ते कदम ही 2047 के स्वर्णिम सपने को साकार करने वाले 'न्यू इंडिया' के संकेत दे रहे हैं।वर्ष 2014 से पहले लंबे समय तक मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित रहा लेकिन 2014 के आम चुनावों में देश की राजनीति ने करवट ली तो उसमें मध्यम वर्ग ने बढ़-चढ़कर अपनी भूमिका सामने रखी।यही कारण है कि पहली बार केंद्र सरकार ने समग्र दृष्टिकोण के साथ विकास की रूपरेखा बनाई।राष्ट्र के विकास के लिए गरीबों को मुख्यधारा में लाने के लिए सामाजिक सहायता की योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित की।वहीं बड़े उद्योगों को भी नीतिगत निर्णयों से सुविधाएं देकर उन्हें विकास का भागीदार बनाया।मध्यम वर्ग, जिसकी चिंता पहले नहीं होती थी, उसे भी विकास का सारथी बनाया जा रहा है।यानी अब मध्यम वर्ग हो या गरीब तबका या उद्यमशील वर्ग, सबका प्रयास की भावना से सबका समुचित विकास सुनिश्चित हो रहा है।2014 के बाद से केंद्र सरकार का प्रयास समाज के उस वर्ग को सशक्त करने का रहा है जिन्हें पहले सरकारी सहायता मिलने में बहुत मुश्किल होती थी।अमृत काल के पहले आम बजट में मध्यम वर्ग के हित में भी अभूतपूर्व निर्णय लिए

बहुत तेजी से बदलते भारत में, विकास हो या व्यवस्था, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सशक्त स्वर्णिम भारत की नींव को इस बार के बजट ने और मजबूती दी है। समर्थ भारत, संपन्न भारत, शक्तिमान भारत, गतिमान भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है।

गए हैं। सात लाख रुपये तक की आय पर आयकर शून्य किए जाने से मध्यम वर्ग में स्वाभाविक उत्साह है। विशेष रूप से 30 वर्ष से कम उम्र के युवा, जिनकी नौकरी नई है, बिजनेस नया है, उनके बैंक खातों में हर महीने अधिक पैसों की बचत सुनिश्चित हुई है।

मध्यम वर्ग के मन की बात

भारत ने राष्ट्रीय मंच पर तेजी से फलते-फूलते हुए मध्यम वर्ग को उभरकर आते हुए देखा है। यह गरीबी रेखा के स्तर में तेज गिरावट के कारण हो सका है जो कि अब आबादी का लगभग 16 प्रतिशत तक कम होगया है। अगर कुल संख्या के लिहाज से देखा जाए तो लगभग एक तिहाई आबादी के मध्यम वर्ग के अंदर आने का अनुमान है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, लघु उद्योग का क्षेत्र हो, नौकरीपेशा वाले लोग हों, करीब-करीब ये सभी लोग भारत का बहुत बड़ा मध्यम वर्ग है। इनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से कहा भी था कि मध्यम वर्ग से निकले हुए प्रोफेशनल्स आज दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। मध्यम वर्ग से निकले हुए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक सभी दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मध्यम वर्ग को जितने अवसर मिलते हैं, वह कई गुणा ताकत के साथ उभर कर आते हैं। इसलिए मध्यम वर्ग को सरकारी दखलंदाजी से मुक्ति चाहिए, मध्यम वर्ग को अनेक नए अवसर चाहिए, उसको खुला मैदान चाहिए। इन्हीं आकांक्षाओं और सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बीते 9 वर्षों से लगातार काम कर रही है। पहली बार देश की राजनीति और शीर्ष नेतृत्वकर्ता ने देश के सामर्थ्य को नई पहचान दी है। जिस मध्यम वर्ग को लंबे समय तक पूरी तरह नकार दिया गया। उसकी तरफ देखा तक नहीं गया। एक प्रकार से वह मान कर चल रहा था कि हमारा कोई नहीं और जो भी करना है अपने बलबूते ही करना होगा, इसी में वह अपनी पूरी शक्ति खपा देता था। केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। आज परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से मध्यम वर्ग को

कितना लाभ हुआ है, इसके कई उदाहरण हैं। 2014 से पहले 1 जीबी डेटा की कीमत 250 रुपये थी जो आज 10 रुपये से भी कम है। आज देश में एक नागरिक औसतन 20 जीबी का उपयोग करता है। अगर उस हिसाब को देखा जाए तो औसतन एक व्यक्ति का 5 हजार रुपये बचता है। भारतीय जन औषधि केंद्र आज पूरे देश में आकर्षण का कारण बने हैं। मध्यम वर्गीय परिवार अपने घर के बड़े-बुजुर्गों के लिए दवा पर जहां एक से तीन हजार रुपए मासिक खर्च करता था वहीं जन औषधि केंद्र पर बाजार में 100 रुपये में मिलने वाली दवाईयां 10-20 रुपये में उपलब्ध हो रही हैं। इन जन औषधि केंद्र से आज 20 हजार करोड़ रुपये मध्यम वर्ग के बचे हैं। मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा करने के लिए शहरी इलाकों में होम लोन की बड़ी व्यवस्था का निर्माण हुआ। रेरा कानून बनाए जाने से मध्यम वर्ग के मेहनत की कमाई अब एक विशेष वर्ग वर्षों तक दबाकर नहीं रख सकता। रेरा ने मध्यम वर्ग को एक नया विश्वास देने का काम किया है। हर मध्यम वर्गीय परिवार के मन में सुरक्षित भविष्य के लिए बच्चे को उच्च शिक्षा देने का एक सपना रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए ही मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल कॉलेज और वहां सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इस प्रयास ने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का नया आधार दिया है। अब उसे यह विश्वास होने लगा है कि उनके बच्चों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित है।

जीएसटी में बहुत तेजी से कराधान कम हुआ है, आयकर कम हुआ है। सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक से जोड़ना, यह अपने आप में मध्यम वर्गीय परिवारों के पैसों को सुरक्षित रखने की गारंटी है। एमएसएमई सेक्टर और कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं, इसका सीधा लाभ मध्यम वर्गीय मेहनतकश परिवारों को हो रहा है। इन सुधारों के कारण हजारों-करोड़ रुपये के विशेष फंड का लाभ व्यापारियों, लघु उद्यमियों को मिल रहा है। आम भारतीय की शक्ति, उसकी ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा आधार है। इस ताकत को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निरंतर काम जारी है। मध्यम वर्ग आज चमत्कार करने की ताकत रखता है। ईज ऑफ लिविंग के लिए हुई सामाजिक योजना वाली पहल से सबसे बड़ा लाभ किसी को होना है तो मध्यम वर्ग के परिवारों को होना है। सस्ते इंटरनेट या सस्ते स्मार्टफोन की बात हो या फिर उड़ान योजना के तहत हवाई जहाज की टिकटों की कीमतें न्यूनतम हो जाने की, राजमार्ग हों, सूचना के अन्य मार्ग हों, यह सभी चीजें मध्यम वर्ग की ताकत को बढ़ाने वाली हैं। जीएसटी से उपभोक्ताओं के कई प्रकार के दैनिक खर्चों में कमी आई है। दैनिक उपयोग की चीजों से लेकर रेस्टोरेंट में खाना खाने जैसी अन्य गतिविधियों तक पहुंच आसान हुई है।

> संविधान और भारत के तिरंगे से हमें प्रेरणा मिलती है- गरीबों को न्याय मिले, जन-जन को आगे बढ़ने का अवसर मिले, निम्न-मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च-मध्यम वर्ग को आगे बढ़ने में कोई रुकावट न आएं, सरकार की अड़चनें न आएं।
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

समग्र सोच के साथ आकांक्षाओं की पूर्ति

प्रबंधन और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार देखा जाए तो मध्यम वर्ग को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है। महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग यानी भारतीय आबादी का एक बड़ा भाग इसके अंतर्गत आता है। वैसे तो आकांक्षी मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होता है और दैनिक जीवन में काफी अनिश्चितताओं का सामना करता है लेकिन वह बेहतर जीवन स्तर की आकांक्षा रखता है। यह टीवी, रेडियो, न्यूज पेपर के साथ सोशल मीडिया और उच्च-आय वर्ग के उपभोग पैटर्न से बहुत प्रभावित होता है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ हुआ है। इन योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (मसलन, पीएम किसान योजना), वित्तीय समावेशन (जैम ट्रिनिटी), एलपीजी सब्सिडी, किफायती आवास, बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण, माइक्रो-हेल्थ इंश्योरेंस और माइक्रो-पेंशन योजनाएं शामिल हैं। इस वर्ग को सर्विस सेक्टर विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अस्थायी रोजगार के विस्तार से भी लाभ हुआ है। जबकि उच्च मध्यम वर्ग को आमतौर पर वित्तीय संपत्तियां, बैंक में जमा और अचल संपत्ति रखने वालों से पहचाना जाता है। इस वर्ग में डॉक्टर, वकील, पेशेवर, चार्टर्ड

अकाउंटेंट आदि आते हैं।मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास की पहचान स्थिर लेकिन कम वेतन वाली नौकरियों के साथ मानी जाती है। इनकी बचत कम होती है और वेतन पर निर्भरता अधिक।इस वर्ग ने पारंपरिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने या उच्च मध्यम वर्ग की तरफ बढ़ने के लिए एक रास्ते के तौर पर देखा है।

मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस को लेकर शुरू से ही गंभीर रही केंद्र सरकार के बारे में आम नागरिक भी यह समझने लगा है कि अब केंद्र में ऐसी सरकार है जो अपने नागरिकों पर भरोसा करती है।केंद्र सरकार ने स्व-सत्यापन को एक सामान्य मानक बनाया, लेकिन इसकी तुलना उस वक्त से करिए जब प्रत्येक फॉर्म या दस्तावेज को प्रमाणित करवाने के लिए लोगों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था। स्व-सत्यापन ने लगभग सभी प्रक्रियाओं को काफी आसान बना दिया है।चाहे वह किसी योजना के लिए पंजीकरण करना हो, प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना हो या लोन के लिए आवेदन जमा करना हो। ज्यादातर सरकारी काम और प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं। डिजिलॉकर की मदद से सुरक्षित, डिजिटल स्टोरेज रखते हुए कई इंटरफेस पर व्यक्तिगत दस्तावेजों को जमा कर वा पाते हैं, सरल और त्वरित आईटी रिटर्न दाखिल कर पाते हैं।यह ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसने जीवन को सरल बना दिया है।भले यह सभी कदम आसान और तार्किक दिखाई देते हों लेकिन उन्हें अमल में लाने में सात दशक लग गए और एक दूरदर्शी नेता के आने तक का वक्त लगा।यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किस तरह से रुकावटों को दूर करने और मध्यम वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के लिए प्रतिबद्ध है ताकि आरंभ से ही विकास को गति प्रदान की जा सके। कुल मिलाकर देखें तो मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं से जुड़े हर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने लगातार राहत देने का प्रयास किया है और मध्यम वर्गीय परिवार की जेब में जितना ज्यादा पैसा बच सके उसका प्रयास किया है।निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सक्रिय रूप से मध्यम वर्ग की चिंताओं का जवाब दे रही है।आज केंद्र सरकार ने न केवल उनकी आकांक्षाओं और जरूरतों को सुना है बल्कि उनके जीवन को आसान बनाने के तरीकों पर निरंतर काम कर रही है ताकि उन्हें मिले अवसर उनकी आकांक्षाओं को नई उड़ान देने का और वे बनें सारथी स्वर्णिम वर्ष के समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न विकसित भारत का।

आइए आगे के पन्नों में जानते हैं कि मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से देश ने समझा है और उसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है...

मध्यम वर्ग की प्रगति यानी संपन्नता, सुरक्षित भविष्य, श्रेष्ठ जीवन और सरलता

पिछले आठ-नौ वर्षों में मध्यम वर्ग के जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने समग्र-व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ काम किया है। कई क्षेत्रों में भारत के बढ़ चढ़कर आते हुए ग्लोबल प्रोफाइल ने हमारे मध्यम वर्ग के बीच एक गौरव की नई भावना पैदा की है। भारत सरकार, दुनिया को एक वैकल्पिक मॉडल प्रदान करते हुए इन चार एस फ्रेमवर्क के जरिए मध्यम वर्ग की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। इन कामयाब कोशिशों को चार 'एस या स' के फ्रेमवर्क में समझा जा सकता है। संपन्नता, सुरक्षित भविष्य, श्रेष्ठ जीवन और सरलता के सिद्धांत पर केंद्र सरकार आकांक्षी मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग को बना रही है विकास का सारथी ...

संपन्नता

मुद्रास्फीति नियंत्रण के जरिए मध्यम वर्ग को समृद्धि का अवसर मिल रहा है। 2014 और 2022 तक के आठ साल में वार्षिक मुद्रास्फीति **4.6 प्रतिशत** रही है जबकि उससे पहले के आठ साल में यह दर **8.7 प्रतिशत** रही थी। कई वैश्विक संकटों के बावजूद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2022 में **5.7 प्रतिशत** पर था जो कई जी-20 देशों की तुलना में बहुत कम था।

आकांक्षी मध्यम वर्ग की डेमोग्राफी के लिए और ज्यादा लिक्विडिटी भी कम ईएमआई के तौर पर आई है। उदाहरण के लिए मई 2014 में छात्रों को मिलने वाले शिक्षा ऋण की ब्याज दर **14 प्रतिशत** थी, वह दिसंबर 2022 तक लगभग **8 प्रतिशत** तक गिर गई थी। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए और ज्यादा ऋण लेना आसान हो गया।

एक देश-एक कर (जीएसटी) पहल से अनुमानित **18 लाख करोड़ रुपये** की सकल बचत हुई है जो सालाना 12 हजार रुपये घरेलू बचत के बराबर है।

पीएम मुद्रा योजना के 38 करोड़ लाभार्थियों में से 12 करोड़ मध्यम वर्ग के लोग थे जिन्हें बिना गिरवी के ऋण के रूप में **7 लाख करोड़ रुपये** मिले थे। मजबूत वित्तीय नीतियों और बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने से वर्ष 2017-18 में एनपीए **11.1 प्रतिशत** से घटकर 2022-23 में **5.8 प्रतिशत** हो गया।

सुरक्षित भविष्य

सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा कर स्वस्थ भविष्य को सुरक्षित करना और उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों ही मोर्चों पर भारत सरकार ने बेहतर परिणामों की दिशा में कदम बढ़ाया है। वहीं उच्च शिक्षा के मोर्चे पर भारत ने देखा है कि पिछले नौ वर्षों में 353 नए विश्वविद्यालय बने। 15 नए एम्स और 261 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 77,386 नई मेडिकल सीट सुनिश्चित हुई है।

- आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का नेतृत्व कर रहा है। 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को कवर करते हुए आयुष्मान भारत गरीब और नव-मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रहा है।
- मध्यम वर्ग के लाखों लोग पहले से ही महत्वपूर्ण दवाओं, स्टेंट और कम लागत पर घुटने के प्रत्यारोपण का लाभ उठा रहे हैं।
- 2023 की ग्लोबल रैंकिंग में 41 भारतीय विश्वविद्यालय को विशिष्ट जगह मिली है जबकि 2014 में यह संख्या केवल नौ थी।
- केंद्र सरकार की पहल का परिणाम है कि भारतीय जन औषधि केंद्र से दवा और चिकित्सीय उपकरण लेने से जनता के 20 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है।
- यह संभव हो पाया 9 हजार जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध 50-90 प्रतिशत सस्ती जेनरिक दवाईयों और 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 87 करोड़ मुफ्त जांच की सुविधा से।

श्रेष्ठ जीवन

आधुनिक विश्व में प्रगति की बुनियाद, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ी होती है। यह मध्यमवर्ग की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की भी पूर्ति करते हैं। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान विकास की गति को भी होता है। शहरी मध्यम वर्ग को भी होता है।

- 2022 तक भारत ने 1.65 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया। देश में सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय में दस गुना बढ़ोतरी के कारण अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बना है।
- भारत के 27 शहरों में अब मेट्रो कनेक्टिविटी है। हम विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होने से एक साल दूर हैं।
- भारत में प्रति व्यक्ति मोबाइल डाटा खपत दर सबसे ज्यादा है और दुनिया में प्रति जीबी डाटा लागत सबसे कम है। हमारे 120 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ता में से लगभग 80 प्रतिशत और 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स को एक साल के अंदर 5जी कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। यह ऑनलाइन शिक्षा, टेली-मेडिसिन और सरकारी सेवाओं की प्रभावी पहुंच के जरिए जबरदस्त लाभ दिलाएगा।

सरलता

- जीवन की सुगमता के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भारत के कैशलेस डिजिटल पेमेंट ईको-सिस्टम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम में से एक माना जाता है।
- 2021-22 में 7,245 करोड़ डिजिटल लेनदेन में यूपीआई की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत थी। पेपरलेस सर्टिफिकेट प्रमाणन के लिए डिजिलॉकर के 14.9 करोड़ उपभोगकर्ता हैं।

दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव का हो अनुभव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया है कि लोगों के जीवन यापन में सुगमता बढ़े। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाना हो या फिर कनेक्टिविटी बढ़ाना, हर स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। पिछले नौ वर्षों में सरकारी कार्यक्रमों ने यह पक्का किया है कि देश के आकांक्षी वर्ग को दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव हो।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार न सिर्फ खर्च बढ़ाया है बल्कि प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के साथ-साथ उसे समय से पूरा भी किया जा रहा है। इससे मध्यम वर्ग के परिवारों को खर्च कम करने में मदद मिली है।
- उड़ान योजना में बहुत सारे टियर-2 और टियर-3 शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ा गया ताकि हवाई यात्रा केवल संपन्न वर्गों तक सीमित न रहे। अब मध्यम वर्ग के पास उड़ान योजना से कम खर्च पर हवाई यात्रा का विकल्प मौजूद है।

मेट्रो रेल

वर्ष 2014 | 5 शहर

वर्ष 2022 | 27 शहर

कार लोन ब्याज दर

- कार लोन का ब्याज दर 2014 में 11% था जो 2022 में घटकर 8% से भी नीचे आया।
- सीएलएसएस ने होम लोन के 48 हजार करोड़ रुपये का बोझ कम किया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत करीब 1.23 करोड़ घरों को स्वीकृति।

मध्यम वर्ग को कर राहत, प्रक्रियाएं भी हुई आसान

स्वर्णिम वर्ष में विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे राष्ट्र में नागरिकों को कानूनी उलझनों से बाहर निकालना, प्रक्रियाएं आसान करना और तकनीक का इस्तेमाल कर पारदर्शिता बढ़ाने का काम तेजी से किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के सर्वसमावेशी और कुशल अर्थनीति के बीच मध्यम वर्ग को कर में बड़ी राहत देते हुए 7 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है।

- नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त।
- आय कर स्लैब 6 से घटाकर 5 किया गया।
- नई कर व्यवस्था में अब 50 हजार रुपये की मानक छूट का लाभ भी मिलेगा।
- नई कर व्यवस्था में 9 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45 हजार रुपये और 15 लाख रुपये आय पर 1.50 लाख रुपये चुकाने होंगे।
- इस वर्ष से डिफॉल्ट रहेगी नई कर व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था चुनने की रहेगी स्वतंत्रता।
- प्रभावी कर दर 2013 में 12.7% थी जो घटकर 2022 में 8.3% हो गई (15 लाख रुपये प्रति वर्ष में)।
- आसान ई-फाइलिंग के साथ अब 16 दिन में प्रक्रिया पूरी और जल्दी रिफंड।
- फेसलेस आकलन और अपील ने दी परेशानी और उत्पीड़न से मुक्ति।
- करदाताओं के चार्टर से उनके अधिकारों का समर्थन।
- आसान अनुपालन के लिए सरल कर व्यवस्था।
- विवाद से विश्वास योजना में 1 लाख करोड़ रुपये के कर विवाद का हुआ निपटारा।

“

मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रॉसेस को सहज, पारदर्शी और तीव्र किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मध्यम वर्ग के जीवन का एक दिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता ही है कि केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग के ईज ऑफ लिविंग को इस तरह सुनिश्चित किया कि सुबह उठने से रात को चैन की नींद और मनोरंजन तक सस्ता, सुलभ और आसान हो। अपना पक्का घर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यम वर्ग को घर खरीदने के लिए लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी गई। बिल्डर से घर समय पर मिले और निवेश सुरक्षित हो, इसकी व्यवस्था RERA में की गई। ऑफिस पहुंचने में देश भर में बढ़ते मेट्रो नेटवर्क ने समय बचाया तो डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट ने सेवाएं सुलभ बना दी।

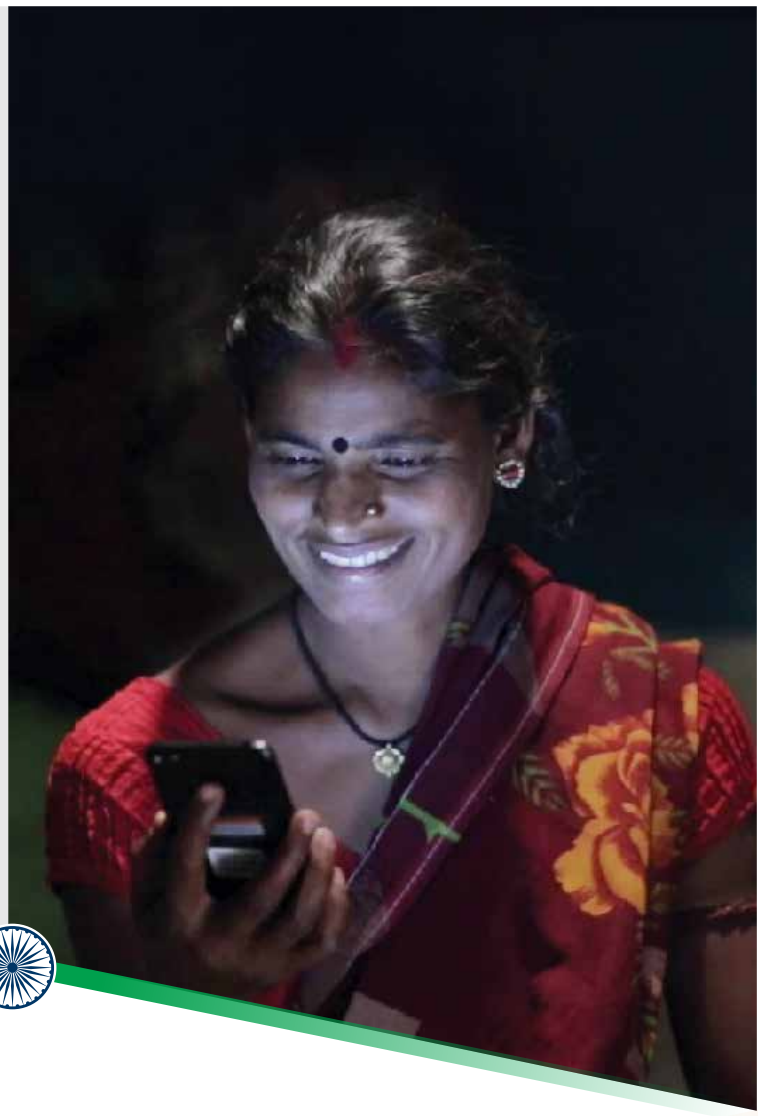

- अपने सपनों का घर, **RERA** के कारण बिल्डर से तय समय पर मिला घर।
- 2.3 लाख रुपये हाउसिंग लोन पर बचे, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम से मिली मदद।
- ई-रिक्शा से पहुंचा मेट्रो, भीम यूपीआई से दिया किराया, समय की हुई बचत।
- 2014 के मुकाबले 5 गुना से अधिक शहरों में मेट्रो सेवा।
- मेट्रो में मोटिवेशनल वीडियो, डाटा की कीमतों में 97% की कमी।
- घर के बाहर खाना, अब जीएसटी मात्र 5%, पहले टैक्स 20% था।
- माता-पिता के लिए जनऔषधि केंद्रों से दवाएं खरीदना, बाजार भाव से 90% तक कीमत कम।
- उजाला एलईडी लाइट से बिजली के बिल में भारी बचत।
- हाउसिंग लोन की ब्याज दरों में कमी से लाखों रुपये की बचत।
- टीवी सेट पर योग का आनंद, मुद्रा लोन से महिला का शुरु हुआ रोजगार।

ईज ऑफ लिविंग के लिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में ऊंची छलांग

वर्ष 2014	वर्ष 2022
83	61

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स टेक्नोलॉजी और डिजिटल समावेशन के स्तर का आकलन करता है। 22 स्थान के सुधार का मतलब- ईज ऑफ लिविंग में सुधार हुआ है।

जीवन की सुगमता का

आधार

जीएसटी से खाना सस्ता

देश की वयस्क आबादी को आधार नंबर जारी करने का काम करीब-करीब पूरा हो गया है। जनवरी, 2023 तक 135 करोड़ से अधिक आधार नंबर जारी किए गए हैं। आमजन के दैनिक जीवन में निरंतर सहायता और सुशासन को मजबूती देने के साथ आधार 'जीवन यापन में आसानी' का माध्यम बन रहा है। वहीं एक देश, एक कर व्यवस्था यानी जीएसटी ने रेस्तरां में खाना भी आसान कर दिया है।

- 135.2 करोड़ आधार नामांकन जेनरेट किए गए।
- 75.3 करोड़ लोगों ने राशन लाभ के लिए राशनकार्ड से आधार लिंक किया।
- 27.9 करोड़ लोगों ने एलपीजी सब्सिडी के लिए कनेक्शन से आधार लिंक किया।
- 75.4 करोड़ बैंक खाते आधार के साथ लिंक किए गए।
- आधार लिंक सिस्टम से 1500 करोड़ से ज्यादा बार किया गया लेनदेन।

रेस्टोरेंट में खाना हुआ सस्ता

1000 रुपये के प्रत्येक बिल पर करीब 150 रुपये की बचत

तब 2014
जीएसटी के पहले

बिल ₹1000

सर्विस चार्ज 10%	= ₹100
सर्विस टैक्स 6.5%	= ₹65
केकेसी 0.2%	= ₹2.2
एसबीसी 0.2%	= ₹2.2
वैट 14.5%	= ₹137.5

कुल = ₹ 1303.5

अब 2022-23
जीएसटी के बाद

बिल ₹1000

सर्विस चार्ज 10%	= ₹100
जीएसटी 5%	= ₹55

कुल = ₹1155

घर खरीददार के हितों की सुरक्षा, बढ़ी डेमोक्रेटाइजिंग कनेक्टिविटी

मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा हो और उसकी कमाई से किया गया निवेश, कानूनी रूप से सुरक्षित रहे इसके लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) बनाई गई। इससे घर खरीददारों के अधिकारों की रक्षा हो रही है तो देरी या अन्य उल्लंघन पर डेवलपर्स मुआवजा देने के लिए भी बाध्य है। डेमोक्रेटाइजिंग कनेक्टिविटी बढ़ी जिससे संचार आसान हुआ।

86, 942

मामलों का निपटारा प्रदेशों द्वारा स्थापित रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों ने किया।

- 2016 के रेरा एक्ट से घर खरीददारों को मिली सुरक्षा।
- बेचे जा रहे मकान के कारपेट एरिया का स्पष्टीकरण।
- देरी पर वित्तीय जुर्माना, खरीददारों की अनुमति के बिना कोई बदलाव नहीं।
- **आवास में मध्यम वर्ग के निवेश की रक्षाः RERA** के बाद बिल्डर करते हैं ब्याज और देरी के लिए मुआवजे का भुगतान।
- 25 हजार करोड़ रुपये का स्वामी निवेश कोष, रुकी हुई परियोजनाओं को शुरू करने में करता है मदद।

डेमोक्रेटाइजिंग कनेक्टिविटी

	तब 2014	अब 2022
इंटरनेट कनेक्शन की संख्या	25.15 करोड़	83.69 करोड़
ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या	6.10 करोड़	81.62 करोड़
एक जीबी डाटा पर खर्च	269 रुपये	10.29 रुपये

उद्यमशीलता और इनोवेशन को बढ़ावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा विकसित राष्ट्र और प्रगति की राह पर तेजी से दौड़ने के लिए तकनीक, उद्यमशीलता और इनोवेशन को बढ़ावा देने का रास्ता खोजते हैं। इसी दिशा में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन सहित कई अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसकी वजह से न सिर्फ स्वरोजगार बढ़ रहा है बल्कि नई नौकरियों का सृजन और चुनौती लेने की ललक भी युवाओं में बढ़ी है।

- वर्ष 2016 में स्टार्टअप की संख्या 445 थी, दिसंबर, 2022 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 86,713 पहुंची।
- मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 46% से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक।
- वर्ष 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे वर्ष 2022 में यूनिकॉर्न की संख्या 108 से अधिक हुई।
- भारत के शुरुआती 100 यूनिकॉर्न का मूल्य 333 अरब डॉलर से अधिक।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जनवरी, 2022 तक 38.58 करोड़ से अधिक लोन दिए गए। इसमें 68% महिला उद्यमी शामिल।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से महज 3 वर्ष में 1.12 करोड़ अतिरिक्त रोजगार का सृजन।
- अटल इनोवेशन मिशन में 2022 तक 10 हजार अटल टिकरिंग लैब स्थापित। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.34 करोड़ लोग प्रशिक्षित।

आईआईएम की बढ़ी संख्या

स्टार्टअप की संख्या

यूनिकॉर्न की संख्या

आईआईटी की बढ़ी संख्या

सर्वसुलभ शिक्षा पर जोर, ऊंचाई की ओर उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने और शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। साथ ही उच्च शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इन कदमों से न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि मेडिकल कॉलेज और सीटों की संख्या भी बढ़ी, आईआईएम, आईआईटी की संख्या बढ़ी तो डिजिटल प्लेटफार्म पर एक्सेस बढ़ने से युवाओं की पढ़ाई हुई सर्वसुलभ।

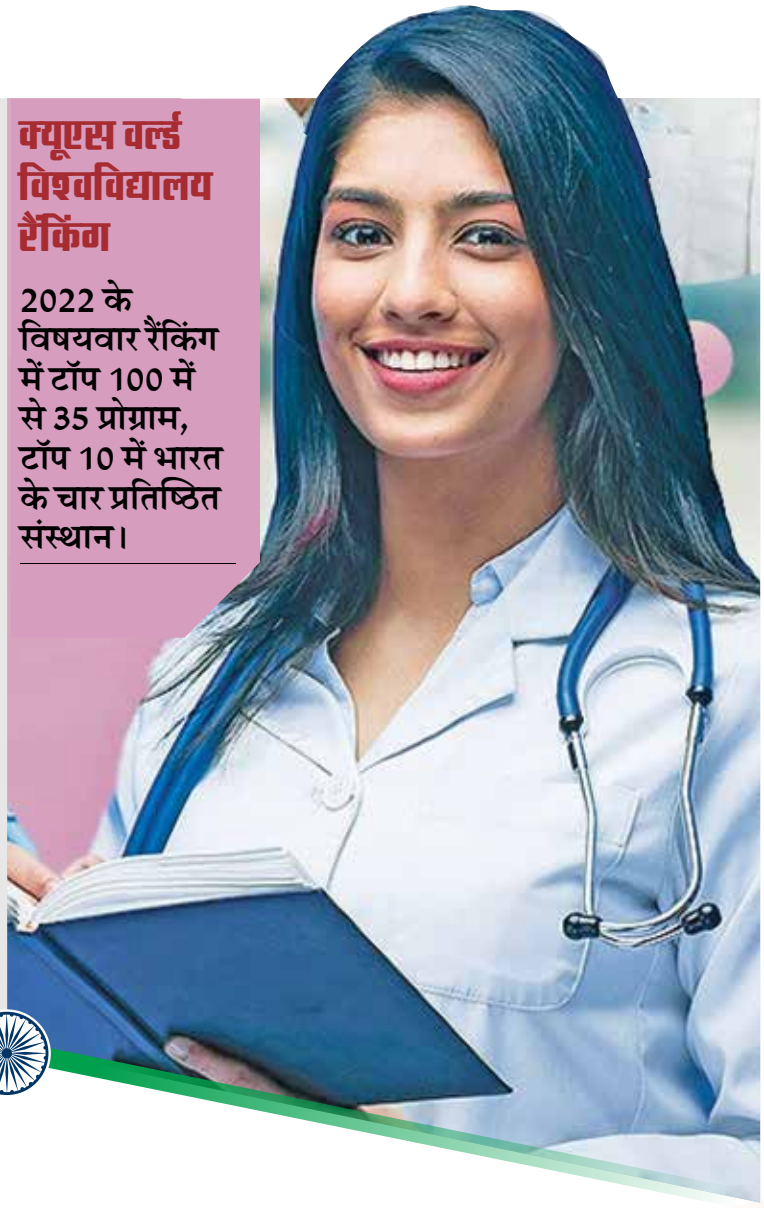

क्यूएस वर्ल्ड विश्वविद्यालय रैंकिंग

2022 के विषयवार रैंकिंग में टॉप 100 में से 35 प्रोग्राम, टॉप 10 में भारत के चार प्रतिष्ठित संस्थान।

- एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफार्म- सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोड वाली पाठ्य पुस्तकें। एक राष्ट्र, एक परीक्षा के साथ एक राष्ट्र, एक टेस्टिंग एजेंसी की हुई शुरुआत।
- शिक्षा वाणी के जरिये रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट सुलभ। न्यूनतम मानकों का निर्धारण कर ओपन, डिस्टेंस और ऑनलाइन शिक्षा के जरिये सुनिश्चित हुई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
- शिक्षा को जारी रखने के लिए स्वयम पोर्टल पर छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है क्रेडिट। गुणवत्तापूर्ण वर्चुअल शिक्षा के लिए दिशा और स्वयम प्रभा टीवी जैसे मंचों का उपयोग।
- बिजनेस और प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के आईआईएमबी और आईआईएमए टॉप 100 संस्थानों में शामिल।
- शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स देशों सहित 45 देशों के साथ विनियम कार्यक्रम को लेकर समझौते हैं। भारत में 2014 से 2022 तक 5,700 से अधिक नए कॉलेज खुले, यानी हर दिन 2 नए कॉलेज खोले गए।

विश्वविद्यालय की बढ़ी संख्या

2014	2022
720	1,043

मेडिकल कॉलेज 70% और सीटें 95% बढ़ी

	कॉलेज	यूजी सीट	पीजी सीट
2014	387	51,348	31,185
2023	655	1,00,163	65,335

राष्ट्र के बड़े काम जिसने दूर की जीवन की कठिनाई

पीएम मोदी के लिए ईज ऑफ लिविंग का मतलब 'केवल विशेष वर्ग' नहीं, बल्कि ग्रामीण, गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाना है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में न सिर्फ राष्ट्र के सपनों को बड़े स्तर पर देखा बल्कि गरीबी से निकल कर मध्यम वर्ग बनने में मदद करने और सुविधा बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को परिपूर्णता (सैचुरेशन) तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम किया।

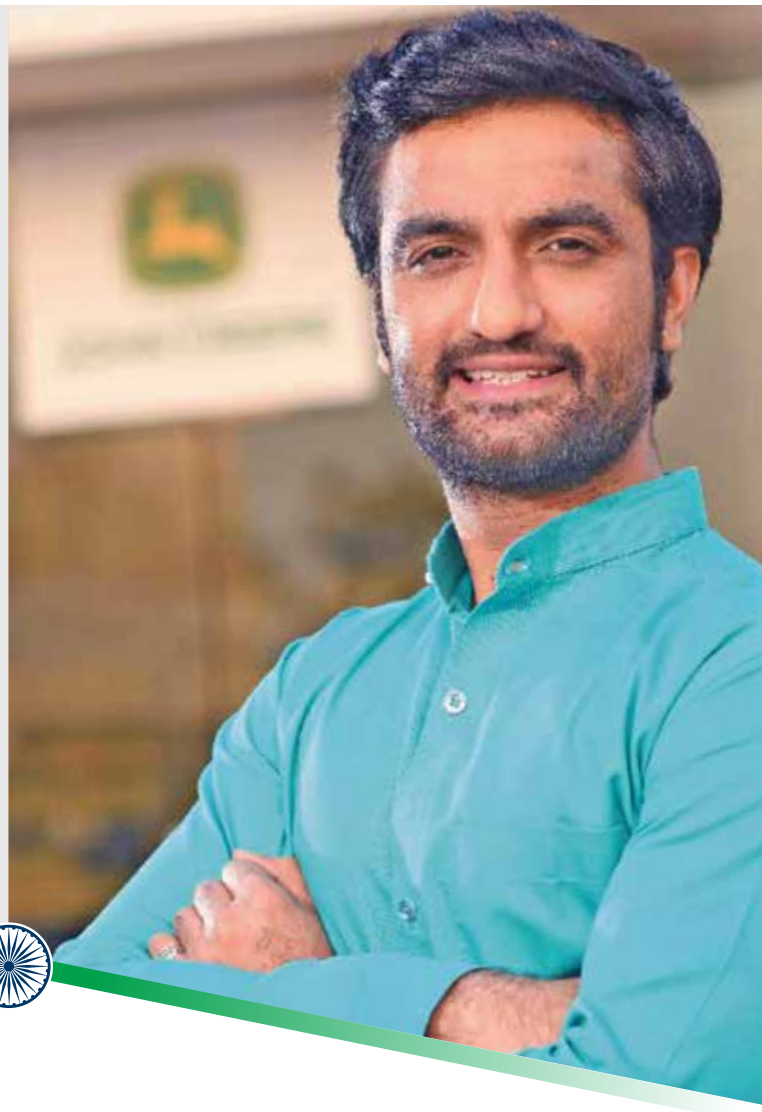

44.6 करोड़
व्यक्तियों को बीमा कवर, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना।

3 करोड़
से ज्यादा शहरी और ग्रामीण घरों का निर्माण, पीएम आवास योजना।

9.6 करोड़
नए गैस कनेक्शन, पीएम उज्ज्वला योजना।

8.07 करोड़
नए नल कनेक्शन करीब साढ़े तीन साल में, जल जीवन मिशन।

1.77 लाख
गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा, भारतनेट।

47.8 करोड़
बैंक खाते, पीएम जनधन योजना।

2.8 करोड़
बिजली कनेक्शन, सौभाग्य योजना।

11.7 करोड़
शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन।

55.5%
बैंक खाते महिलाओं के नाम, पीएम जनधन योजना।

80 करोड़
लोगों को अनाज, पीएम गरीब अन्न योजना।

17.9 करोड़
स्वास्थ्य बीमा कार्ड, आयुष्मान भारत योजना।

20,522
से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंच, उमंग एप।

इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं पर बढ़ा निवेश

इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश न सिर्फ विकसित भारत के सपने को साकार करेगा बल्कि रोजगार के अवसर और मध्यम वर्ग का दायरा भी बढ़ेगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पीएम गतिशक्ति की शुरुआत की और फिर जन जन से जुड़े इंफ्रास्ट्रॅक्चर पर निवेश बढ़ाने का काम किया। इस वर्ष के बजट में चाहे रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा 2.40 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने की बात हो या नए हवाई पोर्ट और एयरपोर्ट की घोषणा या अन्य नागरिक सुविधा वाले प्रोजेक्ट पर खर्च की घोषणा, इनसे मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत मिलेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर
9 साल में 4 गुना बढ़ा बजट

2015-16	2.5 लाख करोड़
2023-24	10 लाख करोड़

सबसे अधिक खर्चः समाज कल्याण, शहरी विकास, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र।

परिवहन
9 साल में 5 गुना बढ़ा बजट

2015-16	85,000 करोड़
2023-24	5,17,000 करोड़

27 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। परिवहन क्षेत्र की 58 सेवाएं ऑनलाइन की गईं।

राष्ट्रीय राजमार्ग
9 साल में 7 गुना बढ़ा बजट

2015-16	23,000 करोड़
2023-24	1,62,000 करोड़

2014 में राजमार्ग की लंबाई 97 हजार किमी थी, 2022 में बढ़कर 1.44 लाख किमी हो गई। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है।

जल जीवन मिशन
12 गुना बढ़ा बजट

शिक्षा
करीब डेढ़ गुना हुआ बजट

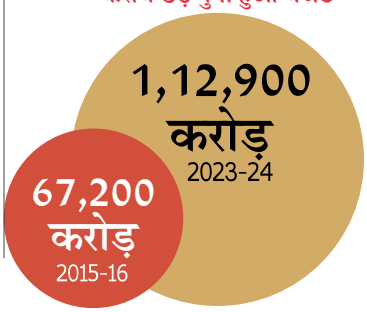

स्वास्थ्य
9 साल में 2.6 गुना बढ़ा बजट

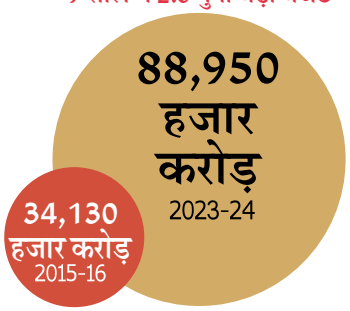

नोटः सभी राशि रुपये में

सोच और अप्रोच बदल भारत ने दुनिया को दिखाया दम

देश और देश के लोगों की बदली सोच और अप्रोच ने न सिर्फ दुनिया को भारत की ताकत का अहसास कराया बल्कि कई मामलों में वैश्विक मंचों पर तारीफ भी हुई। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने भारत की नीति और 'अप्रोच' को अपनाने का भी निर्णय लिया। कोविड महामारी और अन्य वैश्विक चुनौतियों के बीच राष्ट्र ने कैसे आपदा को अवसर में बदला, आने वाले समय में भारत के इस सामर्थ्य की मिसाल दी जाएगी और इस विषय पर अध्ययन किए जाएंगें। आज अगर यह संभव हो पा रहा है तो उसकी वजह है राष्ट्र की सकारात्मक सोच, जिसके दम पर देश बढ़ रहा है आगे...

कोविड के बाद देश-दुनिया और वैश्विक व्यवस्थाएं बदल गई, नई-नई चुनौतियां सामने आई और उससे निपटने का तरीका भी बदल गया। भारत ने बहुत जल्द इन आपदा और चुनौतियों को अवसर में बदला। इसी का नतीजा है कि भारत ने कोविड महामारी, युद्ध और प्राकृतिक चुनौतियों के बाद भी अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। देश ने दुनिया को दिखा दिया कि एंटी-फ्रेजाइल होने का असली मतलब क्या होता है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी को आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में दी। वह कहते हैं कि 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के समय भारत और यहां के लोगों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उसकी स्टडी कर 100 वर्ष बाद मानवता भी खुद पर गर्व करेगी।

2014 में स्थिति ऐसी थी कि लाखों-करोड़ों के घोटालों की वजह से देश की साख दांव पर लगी हुई थी। भ्रष्टाचार की वजह से गरीब अपने हक की चीजों के लिए भी तरस रहा था। युवाओं की आकांक्षा परिवारवाद और भाई-भतीजावाद की बलि चढ़ रही थी। पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में बरसों की देरी हो रही थी। ऐसी सोच और अप्रोच के साथ देश का तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल था। इसी वजह से केंद्र की नई सरकार ने शासन के हर पहलू को फिर से परिभाषित किया और नई सोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखरहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब सरकार की सोच बदली है और उसके अनुसार नीतियां बनाई गई है जिसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। गरीबों के बैंक अकाउंट खुलने लगे और उन्हें बैंक से लोन भी मिलने लगे हैं। गरीबों को अपना घर और संपत्ति का मालिकाना हक मिलने लगा है। शौचालय, बिजली, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन और तेज इंटरनेट कनेक्शन मिलने लगे हैं जिसकी पहले जरूरत ही नहीं समझी जाती थी। केंद्र सरकार अभी तक अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत 28 लाख करोड़ रुपये सीधे गरीबों के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उस बात का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था, "केंद्र की ओर से एक रुपये भेजा जाता है तो वास्तविक लाभार्थी तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं।" इस हिसाब से 24 लाख करोड़ रुपये की राशि किसी और की जेब में चली जाती या कोई लूट लेता था। वर्तमान सरकार के सोचने के इसी नए तरीके की वजह से आज दिल्ली से

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रोजगार मेले का आयोजन, सौंपे नियुक्ति पत्र

केंद्र और राज्य स्तर पर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में बड़े पैमाने पर अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश और 20 फरवरी को उत्तराखंड सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश रोजगार मेले में पुलिस उप निरीक्षकों तथा नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर के समकक्ष पदों एवं अग्निशमन विभाग के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की हुई सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उत्तर प्रदेश रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस नियुक्ति से नौ हजार परिवारों में खुशहाली आएगी और यहां के लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने 20 जनवरी 2023 को अलग-अलग विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे जबकि 22 नवंबर 2022 को देश के 45 से अधिक शहरों में 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी 75,000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे।

एक रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे वास्तविक लाभार्थी के पास पहुंचते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि जिस दिन हर भारतीय के पास शौचालय की सुविधा होगी उस दिन देश विकास की नई ऊंचाई पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कहा तो गया लेकिन समाधान के लिए तत्परता नहीं दिखाई गई। जिसकी वजह से लंबे समय तक देश का बहुत बड़ा हिस्सा मूल सुविधाओं से वंचित रहा। 2014 के बाद से ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता का दायरा 40 से बढ़ कर 100 फीसदी हो गया है। देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई और 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण कराया गया।

वर्ष 2014 से पहले 100 से ज्यादा ऐसे जिले थे जिनको पिछड़ा जिला कहा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार ने पिछड़ेपन की अवधारणा को बदला और नई सोच के साथ इन जिलों को आकांक्षी जिला का नाम दिया गया। अब इन जिलों में अधिकारियों की पोस्टिंग को सजा के रूप में नहीं देखा जा रहा है बल्कि यहां सबसे अच्छे और युवा अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। इन जिलों में अब सब मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं जिसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। सरकार की नई सोच का ही नतीजा है कि अब आंकाक्षी जिलों की स्थिति देश के औसत से अच्छी हो गई है।●

अप्रोच बदली तो नौ साल में दिखा परिणाम

- साढ़े तीन वर्षों में **आठ करोड़** नए घरों में नल से जल पहुंचाया गया।
- भारत में आज प्रतिदिन **38 किलोमीटर** राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है।
- हर दिन **पांच किलोमीटर** से ज्यादा रेल लाइन बिछाई जा रही है।
- एयरपोर्ट की संख्या **74** से बढ़कर **147** हो गई है।
- ग्रामीण इलाकों में लगभग **साढ़े तीन लाख** किलोमीटर सड़क बनाई गई।
- **80 हजार** किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है।
- **तीन करोड़** गरीब परिवारों को पक्के घर दिए गए।
- 2014 के बाद प्रतिमाह **छह किलोमीटर** मेट्रो नेटवर्क बिछाया जा रहा है।
- मेट्रो रूट लेंथ मामले में भारत विश्व में **5वें स्थान** पर है जो कुछ महीनों में **तीसरे स्थान** पर आ जाएगा।
- **128 एयर रूट** को नागरिक विमानों के लिए खुलने से समय और ईंधन दोनों की बचत हुई। इस फैसले से लगभग एक लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ।
- आज दुनिया का **40 फीसदी** रीयल टाइम डिजिटल पेमेंट्स भारत में होता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले

जूट की बोरियों में होगी अनाज की शत-प्रतिशत पैकिंग, 22वें विधि आयोग का बढ़ा कार्यकाल

केंद्र सरकार देश के किसान और नागरिकों को लाभ पहुंचाने एवं उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार सतत प्रयासरत है। इस प्रतिबद्धता की झलक हाल के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले में भी देखने को मिली। इसमें देश के लाखों जूट किसानों के लिए मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया उससे न सिर्फ किसानों को बल्कि जूट मिलों को भी फायदा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाने, गुयाना और भारत के बीच हवाई सेवा समझौता सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी...

फैसला : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए पैकिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग मानदंडों के नियमों को मंजूरी दी। नियमों के अनुसार खाद्यान्न शत-प्रतिशत और चीनी की पैकिंग में 20 प्रतिशत जूट के बैग की अनिवार्यता रहेगी।

प्रभाव: इस फैसले से जूट मिलों और सहायक इकाइयों में कार्यरत 3.7 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। साथ ही, 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम बंगाल को बड़ा लाभ मिलेगा जहां 75 जूट मिलें चलती हैं। बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जूट उद्योग को भी सहायता मिलेगी। सरकार हर साल खाद्यान्न की पैकिंग के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपये के जूट बैग खरीदती है।

फैसला : भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी।

प्रभाव: विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है जिसका गठन भारत सरकार समय-समय पर करती है। वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी को समाप्त हो गया था। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

फैसला : अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क सेवा के विस्तार के लिए भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी।

प्रभाव : गुयाना के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए रूपरेखा तैयार होगी। भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इससे निर्बाध एवं बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, विमान सेवाओं को वाणिज्यिक अवसर मिलेंगे। गुयाना में बड़ी तादाद में भारतीय मौजूद हैं।

फैसला : अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि (शिकागो संधि), 1944 में संशोधन से संबंधित तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि को मंजूरी।

प्रभाव : यह पुष्टि भारत को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेहतर संभावनाएं एवं अवसर प्रदान करेगी। साथ ही, यह पुष्टि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि में निहित सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराती है।●

करदाताओं की पाई-पाई का सही इस्तेमाल हो रहा सुनिश्चित

भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बजट को लेकर कई सुधार किए हैं। संसद में बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी की गई तो बजट कार्यान्वयन में सुधार के लिए बजट के बाद वेबिनार करने का नया विचार सामने आया। जनभागीदारी की भावना से शुरू यह वेबिनार बजट घोषणाओं के प्रभावी, त्वरित एवं निर्बाध कार्यान्वयन में सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी और स्वामित्व को प्रोत्साहित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित "सप्तऋषि" प्राथमिकताओं में से कई विषयों पर फरवरी के महीने में वेबिनार को किया संबोधित...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद फरवरी के महीने में ही कुल पांच वेबिनार को संबोधित किया। इसमें हरित विकास, कृषि एवं सहकारिता, युवा शक्ति का सदुपयोग - कौशल एवं शिक्षा, अंतिम छोर तक पहुंच/कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे, क्षमता का सदुपयोग : प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता लाना जैसे विषय शामिल थे। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित वेबिनार में संबंधित केंद्रीय मंत्री, सरकारी विभागों के प्रमुख हितधारक, नियामक, शिक्षाविद, व्यापार और उद्योग संघों के प्रतिनिधि आदि शामिल हुए। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत, उद्योग जगत के विशेषज्ञों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को एक मंच पर लाने का उद्देश्य बजट घोषणाओं के प्रभावी, त्वरित एवं निर्बाध कार्यान्वयन में संबंधित हितधारकों की भागीदारी और स्वामित्व को आगे बढ़ाना है।

हरित विकास की गति को मिली रफ्तार

हरित विकास केंद्रीय बजट 2023-24 की सात शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है ताकि देश में हरित औद्योगिक और आर्थिक बदलाव, पर्यावरण-अनुकूल कृषि व सतत ऊर्जा के क्षेत्र को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। इससे बड़ी संख्या में हरित रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। हरित विकास को लेकर केंद्रीय बजट में कई परियोजनाओं और पहल की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2014 के बाद देश में पेश किए गए सभी बजट वर्तमान चुनौतियों का समाधान खोजने के साथ-साथ नए युग के सुधारों को आगे बढ़ाते रहे हैं। हरित विकास और ऊर्जा संचरण के जो तीन स्तंभ हैं, उनमें नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, अपनी अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और देश को तेजी से गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना शामिल है।

नौ साल में पांच गुना हुआ कृषि बजट

स्वतंत्रता के बाद भारत का कृषि सेक्टर लंबे समय तक दबाव में रहा लेकिन कृषि का बजट 2014 में 25,000 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर आज 1,25,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो चुका है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में हर बजट को गांव, गरीब और किसान का बजट कहा जाने लगा है। भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नई क्रांति हो रही है। कृषि एवं सहकारिता विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आजादी के बाद लंबे समय तक हम अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए दुनिया पर निर्भर थे लेकिन हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं।"

अमृतकाल के प्रथम बजट में युवाओं को सबसे ज्यादा अहमियत

विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृतयात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। इसलिए अमृतकाल के इस प्रथम बजट में युवाओं को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। 'युवा शक्ति का सदुपयोग - कौशल एवं शिक्षा' विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज भारत को दुनिया मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है। ऐसे में स्किल्ड वर्कफोर्स आज बहुत काम आती है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने वर्षों से हमारे शिक्षा सेक्टर में लचीलेपन का जो अभाव था, उसको बदलने का प्रयास किया है। आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही है, जिससे 'हर स्थान से ज्ञान तक सुगमता' सुनिश्चित हो सके।

अंतिम छोर तक पहुंचने के मंत्र पर इस वर्ष के बजट में विशेष ध्यान

पहले जहां गरीबों को बुनियादी सुविधाओं के लिये सरकार के पीछे दौड़ना पड़ता था वहीं अब सरकार गरीबों के द्वार तक पहुंच रही है। 'अंतिम छोर तक पहुंच' विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "जब हमारा लक्ष्य हर व्यक्ति तक पहुंचना है तब भेदभाव और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी।" इस वर्ष के बजट में जनजातीय और ग्रामीण इलाकों के अंतिम छोर तक पहुंचने के मंत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहली बार, देश इतने बड़े पैमाने पर जनजातीय समाज की विशाल क्षमता को आगे ला रहा है।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने नागरिकों को सशक्त बना रहा भारत

21वीं सदी का भारत प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने नागरिकों को लगातार सशक्त बना रहा है। क्षमता का सदुपयोग : प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता लाने के विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "बीते वर्षों में हमारी सरकार ने हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की 'ईज ऑफ लिविंग' बढ़ाने पर जोर दिया है। इस बार के बजट में भी टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ह्यूमन टच भी प्राथमिकता रही है।" प्रौद्योगिकी, वन नेशन-वन राशन कार्ड, जनधन, आधार और मोबाइल जैसी सुविधाओं का मजबूत आधार बनी जिससे करोड़ों गरीबों को लाभ मिला। तकनीक की मदद और करीब 40 हजार अनुपालनों में कमी करने के साथ पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ●

कर्नाटक में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन

"कर्नाटक की प्रगति का मार्ग रेलवे, रोडवेज, वायुमार्ग और आई-वे की प्रगति से प्रशस्त"

खेती हो, उद्योग हो या फिर बेहतर स्वास्थ्य, सब अच्छी कनेक्टिविटी से और सशक्त होते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने कर्नाटक की कनेक्टिविटी पर बहुत फोकस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को कर्नाटक का दौरा कर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। करोड़ों रुपये की परियोजनाएं कनेक्टिविटी और पानी की आपूर्ति से जुड़ी हुई हैं जिससे राज्य के हर नागरिक को लाभ मिलने वाला है। साथ ही, पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त जारी की जिससे देश भर के आठ करोड़ से ज्यादा किसानों को मिली 16,800 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि...

आत्मनिर्भर और विकसित भारत में कर्नाटक की भागीदारी मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को एक बार फिर कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। नवंबर से फरवरी के बीच कर्नाटक के लोगों से छठी बार कनेक्ट हुए। इस दौरान हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्नाटक के शिवमोगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "बीते कुछ वर्षों में कर्नाटक का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। यह अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। यह प्रगति पथ, रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और डिजिटल कनेक्टिविटी का है।" कर्नाटक में विकास का अभियान अब और तेज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इन विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास

- शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन जिसे लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल भवन प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभालने में सक्षम है।
- शिवमोगा-शिकारीपुरा-रानेबेन्नुर नई रेल लाइन और कोटेगंगुरु रेलवे कोचिंग डिपो की आधारशिला रखी।
- कई सड़क विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया।
- 895 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 44 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
- जल जीवन मिशन के तहत बहु-ग्राम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त जारी

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त में 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 16,800 करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर की गई।
- इस योजना के अन्तर्गत पात्र कृषक परिवारों को 2,000 रुपये की तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। योजना का 100% खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।

बेलगावी में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन भवन राष्ट्र को समर्पित

- करीब 190 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन राष्ट्र को समर्पित।
- लोंडा-बेलगावी-घाटप्रभा खंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित। अनुमानित लागत 930 करोड़ रुपये।
- जल जीवन मिशन के तहत बहु-ग्राम योजना की छह परियोजनाओं का शिलान्यास। योजना पर करीब 1,585 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे 315 से ज्यादा गांवों की 8.8 लाख आबादी को लाभ होगा।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "साल 2019 तक कर्नाटक के गांवों में सिर्फ 25 प्रतिशत परिवारों के घर में नल से पानी के लिए कनेक्शन था। आज कर्नाटक में नल से जल की कवरेज 60 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है।" इतना ही नहीं कर्नाटक के विकास को गति देने के लिए इस समय राज्य में रेलवे के 45 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कर्नाटक के शिवमोगा में 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं बेलगावी में 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आजादी की लड़ाई हो या फिर उसके बाद भारत का नवनिर्माण, कर्नाटक के बेलगावी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85 प्रतिशत छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब-करीब ढाई लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी से ही देश के किसानों को पीएम-किसान की एक और किश्त भेजी। बस एक क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में करीब 16,800 करोड़ रुपये पहुंच गए। ●

आदि महोत्सव

जनजातीय उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव

आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज जब भारत पूरी दुनिया के बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रहे राष्ट्र का बीते 9 वर्षों के दौरान आदिवासी समाज के आर्थिक उत्थान, शिक्षा और सम्मान पर फोकस रहा है। देश के लिए आदि विरासत का अभियान बन चुके आदि महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया उद्घाटन...

जब देश आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता देता है तो प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। वर्तमान केंद्र सरकार वंचितों को वरीयता के मंत्र पर बढ़ चली है जिससे देश विकास के नए आयाम छू रहा है। प्राथमिकता की इस कड़ी में पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें प्राथमिकता देने की विशेष पहल की है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात हो या अलग-

> **मैंने देश के कोने-कोने में आदिवासी समाज और परिवार के साथ कितने ही सप्ताह बिताएं हैं। मैंने आपकी परंपराओं को निकट से देखा है, उन्हें जिया है और उनसे बहुत कुछ सीखा है।**
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

केंद्र सरकार की प्राथमिकता, जनजातीय बच्चों की शिक्षा

- एकलव्य मॉडल अवासीय विद्यालयों की संख्या में 5 गुना की वृद्धि। 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में केवल 90 एकलव्य आवासीय विद्यालय खुले थे। 2014 से जनवरी 2023 तक 690 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए जिनमें 401 शुरू हो चुके हैं।
- 1 लाख से ज्यादा जनजातीय छात्र-छात्राएं इन स्कूलों में पढ़ाई करने लगे हैं। इस साल के बजट में ऐसे स्कूलों में करीब-करीब 40 हजार शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती की भी घोषणा की गई है।
- अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में भी दो गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ 30 लाख विद्यार्थियों को मिल रहा है।
- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 24.10 लाख जनजातीय छात्रों ने दाखिला लिया है।

पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत

- देश में 3 हजार से ज्यादा वनधन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब ऐसे करीब 90 लघु वन उत्पाद हैं, जिन पर सरकार एमएसपी दे रही है। 50 हजार से ज्यादा वनधन स्वयं सहायता समूहों के जरिए लाखों जनजातीय लोगों को इसका लाभ हो रहा है।
- इस समय अलग-अलग राज्यों में 80 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह में सवा करोड़ से ज्यादा जनजातीय सदस्य हैं, बड़ा लाभ महिलाओं को मिल रहा है।
- इस बार के बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम-विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। पीएम-विश्वकर्मा के तहत जनजातीय समुदाय को आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। अपने उत्पाद की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा। देश में नए जनजातीय शोध संस्थान भी खोले जा रहे हैं।
- ट्राइबल उत्पाद ज्यादा बाजार तक आए, इनकी पहचान और डिमांड बढ़े, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। बांस को घास की कैटेगरी में लाया गया और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटाए गए।

जनजातीय उद्यमियों को बाजार से जोड़ने का सशक्त मंच आदि महोत्सव

- देश भर से जनजातीय कारीगरों के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री।
- जनजातीय समुदायों द्वारा उपजाए जाने वाले श्री अन्न और अन्य वन उत्पाद पर विशेष फोकस।
- समृद्ध जनजातीय विविधता एवं जीवंतता को प्रदर्शित करते सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- देश भर के जनजातीय स्वादिष्ट व्यंजन।
- महोत्सव में लगभग 1,000 जनजातीय शिल्पकारों ने भाग लिया।

अलग राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय खोलने का काम, केंद्र सरकार ने न सिर्फ आगे बढ़ कर यह काम किया बल्कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के विकल्प भी खोल दिए हैं ताकि अब हमारे आदिवासी बच्चे और युवा अपनी भाषा में पढ़ाई कर आगे बढ़ सकें। वर्तमान केंद्र सरकार की पहल का ही नतीजा है कि आज देश में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की संख्या में 5 गुना की वृद्धि हुई है। इस बार के बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम-विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की गई। इस वर्ष अनुसूचित जनजातियों के बजट में 2014 की तुलना में 5 गुना वृद्धि की गई है। आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे उन्हें अब 4जी कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, "आदि महोत्सव 'विविधता में एकता' के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने के साथ 'विकास और विरासत' के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। आदि महोत्सव अनंत आकाश की तरह है, जहां भारत की विविधता इंद्रधनुष के रंगों की तरह दिखती है।" यह राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। कार्यक्रम के तहत जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान-पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का उत्सव मनाया जाता है। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइफेड की वार्षिक पहल है।●

भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवंतता विश्व के लिए प्रेरणा

भारत ऐसे समय में जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है जब दुनिया गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। कोविड महामारी एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में जरुरी सुधार नहीं होने की वजह से उनके प्रति विश्वास घटा है। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और मौद्रिक प्रणालियों के संरक्षक के रूप में अब यह जी-20 की जिम्मेदारी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता, विश्वास और विकास को वापस लाएं। यह कोई आसान कार्य नहीं है। आइए जानते हैं इन मुद्दों से निपटने के लिए जी-20 देश किस तरह से समाधान निकालने की कर रहे हैं कोशिश...

जी-20 की अध्यक्षता का बैटल मिलना देश के लिए गर्व का पल रहा, साथ ही जी-20 की ओर से मतभेदों को समाप्त करने और वैश्विक महत्व के मामलों पर सहमति बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। इसके लिए जी-20 के सदस्य राष्ट्र और अतिथि सदस्य राष्ट्र भविष्य की कार्रवाई के क्षेत्रों पर लगातार विचार-विमर्श कर रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के बेंगलुरु में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "अपनी चर्चाओं को दुनिया के सबसे कमजोर नागरिकों पर केंद्रित रखें। वैश्विक आर्थिक नेतृत्व एक समावेशी एजेंडा बनाकर ही दुनिया का विश्वास वापस जीत सकता है।"

जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक

अंतरराष्ट्रीय नीति सहयोग और वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की जताई प्रतिबद्धता

जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से की। बैठक को पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा, "हमारे जी20 की अध्यक्षता का विषय - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य - एक समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। भारत ने अपने डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में अत्यधिक सुरक्षित, अत्यधिक भरोसेमंद और अत्यधिक कुशल सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है। हमारा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम एक निःशुल्क सार्वजनिक कल्याण के रूप में विकसित किया गया है। यूपीआई जैसे उदाहरण कई अन्य देशों के लिए भी आदर्श साबित हो सकते हैं।"

पहली मंत्री-स्तरीय वार्ता में पीएम मोदी ने कहा, "सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति धीमी होती मालूम पड़ रही है जबकि दुनिया की आबादी आठ बिलियन के आंकड़े को पार कर गई है। जलवायु परिवर्तन और उच्च ऋण स्तरों जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने की जरूरत है।"

बैठक की प्रमुख उपलब्धियों में वैश्विक ऋण संकट, जलवायु वित्त, क्रिप्टो पर वैश्विक दृष्टिकोण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, कल के शहरों के वित्तपोषण और कराधान जैसे विषय शामिल रहे।

जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक का सारांश और परिणाम यहां पढ़ें
https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/1st%20FMCBG%20Chair%20Summary.pdf

बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक

जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की पहली बैठक से पहले वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक 22 फरवरी को हुई जिसके उद्घाटन सत्र को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया।

संस्कृति कार्य समूह में चार मुख्य विषयों पर बनी सहमति

मध्य प्रदेश-खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में संस्कृति कार्यसमूह की पहली बैठक 23 से 25 फरवरी तक हुई। भारत की अध्यक्षता में संस्कृति को वैश्विक निरंतरता देने वाली चार प्राथमिकताओं को मजबूती से आगे बढ़ाने पर बैठक में आम सहमति बनी है। इनमें सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और पुनर्निर्माण, सतत भविष्य की जीवंत विरासत का उपयोग करना, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। प्रतिनिधियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी मंदिर समूह और पन्ना टाइगर रिजर्व का भ्रमण कराया गया। संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो के बाद हम्पी, भुवनेश्वर, वाराणसी में आयोजित की जाएंगी।

औरंगाबाद में महिला-20 की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "महिलाओं के नेतृत्व में विकास" की संकल्पना पर जी-20 की अध्यक्षता के दौरान महिला-20 समूह केंद्रित है। यह महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण और इकोसिस्टम बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है जिसमें महिलाओं की पूरी क्षमता का पता चल सके और उनके जीवन के साथ-साथ दूसरे का भी जीवन बदले। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 27-28 फरवरी, 2023 को महिला-20 की पहली बैठक आयोजित की गई। महिला-20 की पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं-उद्यमिता में महिलाएं, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास के अलावा जलवायु लचीलेपन कार्य में परिवर्तन निर्माताओं के रूप में महिलाएं और लड़कियां। महिला-20 की 13-14 अप्रैल को राजस्थान के जयपुर में दो अन्य अंतरराष्ट्रीय बैठकें होंगी। इसके बाद 15-16 जून को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इसका शिखर सम्मेलन होगा।

युवा-20 कार्य समूह

'साझा भविष्य: लोकतंत्र और शासन में युवा' मंथन

जी-20 के युवा-20 कार्य समूह के तहत 22 फरवरी को 'साझा भविष्य: लोकतंत्र और शासन में युवा' विषय पर मंथन कार्यशाला आयोजित की गई। नई दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आयोजित विचार मंथन में 'डिजिटल इंडिया', 'विद्यार्थी-केंद्रित शासन,' और 'नीति क्षेत्र' विषय पर चर्चा में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के महत्वाकांक्षी और अनुभवी दोनों तरह के उद्यमी शामिल हुए।●

नए भारत में वैश्विक होती हिंदी...

वैश्विक एजेंडे को आकार दे रहा नया भारत, दुनिया को यह बताना चाहता है कि हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं बल्कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के साथ चलने और नई तकनीक से कदम मिलाने में सक्षम है। इसकी गवाही विश्व भर में हिंदी बोलने वाले 80 करोड़ से अधिक लोग दे रहे हैं। यह केवल भारत के करीब 45% आबादी की भाषा नहीं है बल्कि दुनियाभर में बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार के लिए 15 से 17 फरवरी तक फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का किया गया आयोजन...

भारत के लिए यह कहावत आम है... कोस-कोस में पानी बदले, चार कोस में वाणी। बोली-भाषा की विविधता के बीच हिंदी ने अपनी एक विशेष जगह बनाई है। हिंदी ने न सिर्फ पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया बल्कि आजादी में एक मुखर और संपर्क भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हिंदी वैश्विक होती जा रही है और इसे बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैश्वीकरण और बाजारवाद के संदर्भ में हिंदी का महत्व लगातार बढ़ रहा है क्योंकि 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा भारत, आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत स्तंभ बन रहा है।

वर्ल्ड लैंग्वेज के 22वें संस्करण इथोनोलॉज के अनुसार विश्व में हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। न्यूजीलैंड, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, मलेशिया, थाइलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मॉरिशस, सूरीनाम जैसे देशों में हिंदी बोली जाती है तो फिजी ऐसा देश है जहां न केवल हिंदी भाषा बोली जाती है बल्कि इसका अस्तित्व वहां की आधिकारिक भाषा के रूप में कायम है। 10 जून, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी कामकाज और जरूरी सूचनाएं 6 आधिकारिक भाषाओं के अलावा हिंदी में भी जारी होंगे। यह हिंदी की बढ़ती साख और लोकप्रियता को दर्शाता है।

भारत सरकार विदेशों में हिंदी दिवस का आयोजन कर रही है तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। मूल परंपरा, विरासत और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए अपनी भाषा में बातचीत करना ज्यादा कारगर होती है। 12वें हिंदी सम्मेलन की भारत सरकार के साथ सह-मेजबानी कर रहे फिजी में करीब 30 फीसदी भारतीय मूल के लोग हैं। फिजी में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया लेकिन इससे पहले 11 सम्मेलन भारत के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, मॉरिशस में हुए हैं। इस सम्मेलन में स्मारक डाक टिकट और हिंदी की छह पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।

सम्मेलन का उद्घाटन फिजी के राष्ट्रपति महामहिम रातु विलियम कटोनिवेरे और भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन का मुख्य विषय "हिंदीः पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक" था जिसके 10 अकादमिक सत्रों में 31 से अधिक देशों के 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सम्मेलन में फिजी और प्रशांत क्षेत्र तथा गिरमिटिया देशों में हिंदी की स्थिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिनेमा और साहित्य का हिंदी पर प्रभाव, हिंदी के अध्यापन और प्रगति पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सम्मेलन के उद्घाटन पर कहा, "आज विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हिंदी बोलने वालों की बढ़ती संख्या हिंदी के वैश्वीकरण का प्रमाण है। यह समारोह दर्शाता है कि भाषा न केवल पहचान की अभिव्यक्ति है बल्कि भारत और अन्य देशों को जोड़ने का माध्यम भी है। जब भाषा और संस्कृति का संगम दुनिया देखती है तो विश्व कल्याण के लिए यह अच्छा ही तो है!"

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया, "वह युग पीछे छूट गया जब पश्चिमीकरण को प्रगति का आधार माना जाता था। ऐसी कई भाषाएं और परंपराएं जो औपनिवेशिक युग के दौरान दबा दी गई थी अब एक बार फिर वैश्विक मंच पर आवाज उठा रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि विश्व को सभी संस्कृति और समाज के बारे में अच्छी जानकारी हो। इसलिए हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के शिक्षण और प्रयोग को व्यापक बनाना बहुत जरूरी है।" ●

फिजी में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन

- भारत और फिजी के बीच राजनयिक के साथ-साथ प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंध है।
- भारत से अनुबंध के तहत 143 वर्ष पहले गन्ने के खेत में काम करने के लिए हजारों श्रमिकों को फिजी ले जाया गया था। उस समय फिजी और भारत पर अंग्रेजी शासन था।
- फिजी ले जाए गए लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के थे। फिजी की हिंदी में अवध क्षेत्र का प्रभाव दिखता है। फिजी में बसे उन हिंदुस्तानियों की आज की पीढ़ी भारतीय विरासत पर गर्व करती है।
- फिजी में हिंदी की शुरूआत 1879 से 1916 के बीच मानी जाती है। हिंदुस्तानी पूर्वजों के कारण हिंदी ने यहां अपना विशेष स्थान बना रखा है।
- हिंदी भाषा न सिर्फ यहां के प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है बल्कि फिजी के संविधान में भी इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल है।
- संयुक्त राष्ट्र (2020) के अनुसार, फिजी की जनसंख्या करीब 8,96,000 है और उनमें से 30 प्रतिशत से अधिक लोग भारतीय मूल के हैं।

विश्व हिंदी सम्मेलन का हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में योगदान

- मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय और वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।
- वैश्विक स्तर पर हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन होता है।
- विश्व के कई देशों में हिंदी पीठों की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की सूचना प्रसारण प्रणाली में हिंदी का लगातार प्रयोग बढ़ रहा है।
- यह सम्मेलन प्रवासी भारतीय और भारतवंशियों से भारत के संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं।

'सम्मान' पाकर मेहनत करने की और मिलती है ताकत

मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, आपको परिश्रम की ताकत पहचाननी होगी। सच्ची लगन से यदि आप काम में लगे हैं तो देर-सबेर आपके काम को सम्मान मिलेगा ही। वर्ष 2023 में घोषित पद्म सम्मान में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो इस बात का जीवंत उदाहरण है। कोई 50 तो कोई 60 वर्ष से अपने-अपने क्षेत्र में बिना किसी प्रचार-प्रसार के काम में जुटे हैं। इन्होंने अपने काम से न सिर्फ भारत की विरासत बल्कि कला-संस्कृति, खेल और लोक संगीत को जीवंत रखा है बल्कि अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। ***पद्म सम्मान पाने वाले ऐसे ही कुछ शख्सियतों से न्यू इंडिया समाचार ने की है बात...***

गुरचरण सिंह

उम्र 87 वर्ष, जज्बा... मैदान पर प्रैक्टिस कराने का

दोपहर के करीब साढ़े तीन बजे थे, इनके मोबाइल पर कॉल किया तो फोन किसी और ने उठाया। उनसे पूछा कि गुरचरण सिंह जी से बात हो सकती है ?तो उन्होंने कहा एक मिनट होल्ड करें अभी मैदान पर लड़कों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। एक मिनट के अंदर ही वे फोन पर आ गए और कहा- जी बोलिये। मैंने कहा इस उम्र में भी इस समय ग्राउंड पर तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। भगवान के आशीर्वाद से शरीर साथ दे रहा है तो जो क्रिकेट मेरे अंदर बचा है नए जेनरेशन को दे रहा हूं। क्रिकेट ही मेरा जीवन है।

भारतीय क्रिकेट टीम को अजय जडेजा, मनिंदर सिंह, सुरेंद्र खन्ना, कीर्ति आजाद, मुरली कार्तिक और विवेक राजदान जैसे क्रिकेटर देने वाले 87 वर्षीय गुरचरण सिंह कहते हैं कि जो मिला है बहुत मिला है। सम्मान मिलने में कोई देरी नहीं हुई है। इस उम्र में सम्मान मिलने का एक फायदा यह भी है कि काम करने की और ताकत मिलेगी। अविभाजित भारत के लाहौर में जन्म लेने वाले गुरचरण सिंह विभाजन के समय हिंदुस्तान आ गए। उस वक्त से ही क्रिकेट को अपना जीवन बना लिया। पद्म सम्मान से पहले इन्हें वर्ष 1987 में द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1985 से 87 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे, रणजी ट्रॉफी, अंडर-22 और अंडर-19 के खिलाड़ियों को कोचिंग दी। इंडियन रेलवे क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रहे। दिल्ली के कई स्कूलों में कोचिंग दी है और आज भी बच्चों के साथ 12 से 14 घंटे ग्राउंड पर ही बिताते हैं।

कपिल देव प्रसाद

बावन बूटी के शिल्पकार... उम्मीद अब बढ़ेगा बाजार

बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले 68 वर्षीय कपिल देव प्रसाद ने दादा और पिता से जो बावन बूटी का हुनर सीखा उसे 15 वर्ष की उम्र से ही न सिर्फ स्वरोजगार का एक माध्यम बनाया है बल्कि विरासत की इस कला को भी

संभाल रहे हैं। इन्होंने 125 लोगों की एक टीम तैयार की है जो इस कला का उपयोग करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि, कपिल देव कहते हैं कि इस कला की बारीकी और हुनर को पहचानने वाले लोग कम हैं। मशीनी कपड़े बाजार पर हावी हैं जिससे बावन बूटी का बाजार कमजोर होता है और उपभोक्ता भी कम होते हैं। हालांकि वह मानते हैं कि जब से इस कला की वजह से मुझे पद्म सम्मान देने की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की गई है ऐसा लगने लगा है कि इसके बारे में लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसका बाजार भी बढ़ेगा। बावन बूटी का उपयोग साड़ी के अलावा बेड कवर और पर्दे पर भी किया जा रहा है। बूटियों में बौद्ध धर्म-संस्कृति के प्रतीक चिन्हों की बारीक कारीगरी होती है। बावन बूटी में कमल का फूल, बोधि वृक्ष, बैल, त्रिशूल, सुनहरी मछली, धर्म का पहिया और शंख जैसे प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसकी साड़ियों की मांग भी ज्यादा रहती है।

कर्मा वांगचू

जो थे...अरुणाचल में शिक्षा, संस्कृति के सेवादार

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाज सेवक कर्मा वांगचू को मरणोपरांत पद्म श्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। कर्मा वांगचू, तवांग जिले से पहले व्यक्ति थे जो राज्य सरकार में मंत्री बने। हालांकि वर्ष 1994 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान हो या इसके बाद, तवांग और आसपास के इलाकों में पिछले 50 वर्षों से समाज सेवा कर रहे थे। इन्होंने इंडो तिब्बत फ्रेंडशिप सोसायटी की स्थापना की। इनकी मदद से ही तवांग के सीमावर्ती गांवों में 1250 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। वांगचू ने सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी अथक प्रयास और लोगों की सेवा की।

हेम चंद्र गोस्वामी

विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में लगी जिनके मुखौटों की प्रदर्शनी

असम के कला और सांस्कृतिक इतिहास से परिचित किसी भी व्यक्ति के लिए हेम चंद्र गोस्वामी कोई नया नाम नहीं है। गोस्वामी ने पूरे विश्व में राज्य की 'मुखा' परंपराओं को पुनर्जीवित करने और दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 64 वर्षीय गोस्वामी को वर्ष 2023 का पद्म श्री सम्मान देने का निर्णय लिया गया है। इन्हें मानव मुख, पशु, पक्षी, देवताओं और राक्षसों सहित विभिन्न प्रकार के चरित्रों को चित्रित करके पारंपरिक मुखौटे बनाने में महारत हासिल है। हेम चंद्र गोस्वामी ने वर्ष 1984 में सुकुमार कला केंद्र की स्थापना की। इनकी ओर से 100 से अधिक विद्यार्थियों को मुखौटा शिल्प बनाने में प्रशिक्षण दिया गया है। इनके द्वारा तैयार किए गए मुखौटा की लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में प्रदर्शनी लगाई गई। देश के साथ-साथ फ्रांस, जर्मनी, इजराइल के बच्चों को भी अपनी यह कला सिखाई। इसके अलावा सत्रीया नृत्य और बरगीत संगीत का प्रशिक्षण भी इनकी ओर से दिया जा रहा है।●

ऑपरेशन दोस्त

मानवता के प्रति भारत के समर्पण और प्रतिबद्धता का दर्शन

भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दुनिया में भी बना भरोसे का प्रतीक

देश ही नहीं, दुनिया में भी जब कभी आपदा आई, भारत मानवता के प्रति पहले मददगार के रूप में सामने आया। चाहे नेपाल का भूकंप हो या मालदीव संकट, श्रीलंका में संकट हो या फिर कोविड आपदा के समय दुनिया के लिए औषधि का केंद्र बनना। अब तुर्किए-सीरिया में आए भयावह भूकंप के बाद 'ऑपरेशन दोस्त' अभियान चलाकर मदद के लिए भारतीय बचाव दल का सबसे पहले पहुंचना। कुशलता और संवेदनशीलता का परिचय देकर मानवीय चेहरा बने तुर्किए-सीरिया से लौटे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संवाद ...

> तुर्किए हो या फिर सीरिया, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रकटीकरण किया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है।
>
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

"जब मैं राउंड ले रहा था तो एक मरीज का रिश्तेदार देखकर समझ गया कि मैं यहां का कमांडिंग ऑफिसर हूं। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर आंखों से लगाया और चूमा। मैं भी झुक गया। उसने कहा कि आप समझ सकते हैं यह क्या है? तो मैंने कहा, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो वह कहता है, नहीं आप मेरे पिता समान हैं यह सुनकर मैं गदगद हो गया। फिर उसने कहा कि सर मैं इस देश की युवा पीढ़ी हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया है।"

"एक महिला कह रही थी कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है लेकिन आज की तारीख में मेरे लिए दूसरे नंबर पर आप हो।"

"हमारे स्वॉन ने वहां भी अच्छा काम किया। स्वान दस्ते की मदद से कई जीवितों को बाहर निकाला।"

"जब हम वहां से निकल रहे थे लोग वहां रो रहे थे।"

"मरीज अस्पताल से बाहर जाते हुए भगवान को धन्यवाद करते हुए कह रहे थे कि जितना हम अपने भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, उतना ही आपका भी धन्यवाद।"

"भारतीय वायुसेना का ग्लोबमास्टर जहां भी उतरता है वहां लोगों को भरोसा होता है कि मदद आ गई है। भारत के प्रति भरोसा है कि वह पूरी तरह से मदद करेगा।"

यह है 'ऑपरेशन दोस्त' की शौर्य गाथा, जिसे तुर्किए-सीरिया की भूकंप आपदा में राहत बचाव कर लौटी भारत की थल सेना, वायु सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किया। यह नए भारत की वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से भरी उस संवेदना को दिखाता है जिसके लिए देश हो या दुनिया, मानव हित सर्वोपरि है। भारतीय तिरंगे के साथ जब कोई दूसरे देश में पहुंचता है तो उस देश के नागरिकों को भी भरोसा हो जाता है कि अब उनकी मदद हो जाएगी। बीते कुछ वर्षों में भारत की इस छवि का एक और उदाहरण दुनिया ने तुर्किए-सीरिया में भूकंप की आपदा के बाद फिर से देखा। किसी भी आपदा के समय बचाव के लिए 'गोल्डन ऑवर' का बहुत महत्व है और भारत के बचाव दल ने बेहद कम समय में तैयारी कर कुशल रणनीति के साथ जिस तरह से तुर्किए-सीरिया में बचाव अभियान चलाया, उसने इस देश के नागरिकों का भी दिल जीत लिया। पहली बार इस तरह के बचाव अभियान में महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया, जिसकी सराहना हो रही है।

दरअसल, जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो उन्हें आत्मनिर्भर कह सकते हैं लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वह निःस्वार्थ होता है। यह बात केवल व्यक्तियों

आपदा प्रबंधन पहले केवल कृषि विभाग का हिस्सा हुआ करता था क्योंकि तब आपदा का मतलब समझा जाता था- बाढ़ या सूखा। हालांकि, भुज में आए भूकंप से सबक लेकर 2003 में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गुजरात आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया। बाद में इसी से प्रेरणा लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2005 में पूरे देश के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया।

तुर्किए में एनडीआरएफ ने जीता दिल, बचावकर्मियों ने दिया अभूतपूर्व और प्रेरक योगदान

- 6 फरवरी को तुर्किए में आए भीषण भूकंप के बाद कुछ ही मिनटों में भारत ने अपनी टीम को वहां जाने के लिए कहा और 48 घंटे से भी कम समय में टीम को तुर्किए भेजा गया।
- 'आपदा सेवा सदैव सर्वत्र' के मूलमंत्र पर काम करते हुए एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां भेजी गई थीं। 3 टीम में 152 बचावकर्मी भेजे गए थे जिसमें से 5 महिला बचावकर्मी भी शामिल थीं।
- इस पूरे अभियान में भारत की महिला बचावकर्मियों ने अभूतपूर्व और प्रेरक योगदान दिया। पीड़ित क्षेत्रों के लोगों ने जब भारतीय महिलाओं को बचाव दल की वर्दी में देखा तो न सिर्फ उनकी सराहना की बल्कि उन्हें अत्यंत सम्मान और प्यार भी दिया।
- ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय वायु सेना के तीन C17 ग्लोबमास्टर हवाई जहाज से एनडीआरएफ अपने साजो-सामान और 11 गाड़ियां के साथ आपदाग्रस्त क्षेत्र पहुंचा।
- यह टीम पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी और उनके पास दवाइयां, टेंट, राशन और ईंधन की पूरी व्यवस्था थी ताकि वहां का स्थानीय प्रशासन निश्चिंत रहे।
- एनडीआरएफ की टीम के साथ डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और इंजीनियर सहित अन्य प्रशिक्षित कर्मी थे। साथ में, छह स्वान दस्ता भी था। टीम में काफी प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम मैनपावर को शामिल किया गया था।
- एनडीआरएफ टीम की मदद से दो लड़कियों को जीवित बचाया गया। इसमें से एक छह साल और दूसरी आठ साल की थी। साथ ही, बचाव दल ने 85 शवों को बरामद किया।
- यह पूरा अभियान गृह, विदेश एवं रक्षा मंत्रालयों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साझे प्रयास से ही संभव हो सका। 2011 में जापान और 2015 में नेपाल में आए भूकंप में भी भारत से एनडीआरएफ की टीम सहायता के लिए गई थी।

पर ही नहीं, राष्ट्रों पर भी लागू होती है। इसलिए भारत ने बीते वर्षों में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ निःस्वार्थ देश की पहचान को भी सशक्त किया है। तुर्किए-सीरिया की आपदा के समय भारत ने जितनी तेजी से राहत पहुंचाई वह आपदा प्रबंधन को लेकर उसकी तैयारियों को दर्शाता है। इसने विश्व जगत का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। अब भारत की सोच आपदा के समय राहत और बचाव की क्षमता को अधिक मजबूत करने की है ताकि वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राहत और बचाव दल की अपनी पहचान को सशक्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, "हमारी खुद की तैयारी जितनी बेहतर होगी, हम दुनिया की भी उतनी ही अच्छी तरीके से सेवा कर पाएंगे।" भारतीय दल की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की ओर से उन्हें सैल्यूट किया।

निश्चित तौर से बीते कुछ वर्षों में हर आपदा में दुनिया ने भारत का दम देखा है। मुआवजे और राहत सामग्री के वितरण से आगे निकलकर चुनौतियों का बेहतरीन तरीके से सामना कर नुकसान को काफी हद तक कम करने में सफलता हासिल की है।●

आज़ादी का अमृत महोत्सव

आजादी के लिए समग्र भारत में जगाई चेतना की मशाल

आजादी की लड़ाई में मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक राष्ट्र भक्तों ने प्राण न्यौछावर करने का रास्ता चुना था। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के आदर्शों पर चलते हुए स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को जोड़ने का काम किया और अपने संकल्प की पूर्ति के लिए पल-पल जीने का रास्ता चुना। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने न सिर्फ आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी बल्कि जन-जन को जागृत करने का भी काम किया। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे हेमू कालाणी, चारुचंद्र बोस, पंडित कांशीराम और हनुमान प्रसाद पोद्दार जिन्होंने अपने बलिदान, त्याग और तपस्या से समग्र भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को चेतना देने का किया काम...

हनुमान प्रसाद पोद्दार : हथियारों के जखीरे को लूटकर छिपाने के लिए दर्ज हुआ था राजद्रोह का मामला

जन्म : 17 सितंबर 1892, मृत्यु : 22 मार्च 1971

लोगों के बीच 'भाई जी' के नाम से लोकप्रिय हनुमान प्रसाद पोद्दार का जन्म 17 सितंबर 1892 को हुआ था। आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कई तरह के अत्याचार के बावजूद वह अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके। महज 13 वर्ष की आयु में हनुमान प्रसाद पोद्दार का बाल मन, कलकत्ता में अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह कर उठा। 19 जुलाई 1905 में लार्ड कर्जन द्वारा बंग भंग की घोषणा के बाद जब मां भारती के सपूतों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का निर्णय लिया तो इस आंदोलन के साथ भाई जी भी जुड़ गए। उन्होंने विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए संघर्ष छेड़ने के साथ खादी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। 16 जुलाई 1914 को उन्हें तीन साथियों सहित राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आरोप लगा कि इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के हथियारों के जखीरे को लूटकर उसे छिपाने में मदद की थी।

इस समय उनके खास शुभचिंतकों ने भी अंग्रेजों के भय से साथ छोड़ दिया था लेकिन उन्होंने हार माने बिना अपनी लड़ाई जारी रखी। कलकत्ता में वह स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों अरविंद घोष, देशबंधु चितरंजन दास, पं. झाबरमल शर्मा के संपर्क में आए और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। इसके बाद लोकमान्य बालगंगाधर तिलक और गोपालकृष्ण गोखले जब कलकत्ता आए तो भाई जी उनके संपर्क में आए। महात्मा गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। बाद में वह जमनालाल बजाज की प्रेरणा से मुंबई चले आए। यहां वह वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेव देसाई और कृष्णदास जाजू जैसी विभूतियों के संपर्क में आए। इतना ही नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन संग्रह करने के लिए कलकत्ता आए तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कई लोगों से मिलकर इस कार्य के लिए दान राशि दिलवाई।

मुंबई में रहते हुए उन्होंने अग्रवाल नवयुवकों को संगठित कर मारवाड़ी खादी प्रचार मंडल की स्थापना भी की थी। हिंदू धर्म ग्रंथों में होने वाली अशुद्धियों को दूर करने और लोगों को कम दाम पर पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने अपने मौसेरे भाई जयदयाल गोयन्दका की मदद से गीता प्रेस की स्थापना की। गीता प्रेस शब्द जेहन में आते ही एक तस्वीर उभर कर सामने आती है और मानस को भारतीयता से भर देती है। भारत वर्ष की महान प्राचीन गौरवशाली परंपरा और आधार ग्रंथों के बारे में पूरी दुनिया को आज अगर कोई भी जानकारी मिल सकती है तो यह इस महान संस्थान की ही देन है। रामचरित मानस और श्रीमद्भागवत गीता जैसे ग्रंथ जनमानस को उपलब्ध कराने में गीता प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

22 मार्च 1971 को हनुमान प्रसाद पोद्दार का निधन हो गया। 15 मई 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान प्रसाद पोद्दार का स्मरण कर श्रद्धांजलि दी और कहा था, "हनुमान प्रसाद पोद्दार आधुनिक भारत के सांस्कृतिक इतिहास के महाप्रणेता हैं। वह भारत की स्वाधीनता संग्राम के योद्धा तो थे ही, उससे भी बड़े वह भारतीय संस्कृति के संवाहक बन कर लड़ रहे थे। जब देश में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, तब भारतीय सनातन संस्कृति को आधार बनाकर भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने प्रकाशन एवं पत्रकारिता की नींव रखी थी।"

पंडित कांशीराम : देश की आजादी के लिए भारत से लेकर अमेरिका तक किया काम

जन्म : 13 अक्टूबर 1883, मृत्यु : 27 मार्च 1915

गदर पार्टी के प्रमुख नेता और देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पंडित कांशीराम का जन्म 13 अक्टूबर 1883 को पंजाब के अंबाला जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित गंगाराम था। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने तार भेजने का काम सीखा और कुछ दिन अंबाला और फिर दिल्ली में तारबाबू के तौर पर नौकरी की। बाद में वह अमेरिका चले गए। यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। यहीं उनकी मुलाकात सोहन सिंह भकना से हुई। कांशीराम और सोहन सिंह भकना जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अमेरिका में पंडित कांशीराम ने आजीविका के लिए ठेकेदारी का काम किया। साथ ही वह भारत की आजादी की खातिर कुछ संगठनों में भी शामिल हो गए और लोगों को प्रेरित करने लगे। यह संगठन भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए बनाए गए थे। अमेरिका में ही पंडित कांशीराम की मुलाकात करतार सिंह सराभा से भी हुई थी। पंडित कांशीराम पर लाला हरदयाल का बहुत प्रभाव था। 1913 में पंडित कांशीराम को 'गदर पार्टी' का कोषाध्यक्ष बनाया गया जिसका भारतीय स्वाधीनता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस समय यूरोप में प्रथम विश्वयुद्ध के बादल मंडरा रहे थे उसी समय गदर पार्टी ने निश्चय किया कि कुछ लोगों को अमेरिका से भारत वापस जाना चाहिए ताकि वहां जाकर देश की आजादी के लिए काम किया जा सके। इसी योजना के अंतर्गत पंडित कांशीराम भी भारत आए। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने और उसे उखाड़ फेंकने के लिए लोगों को प्रेरित किया। कांशीराम लुधियाना जिले में काम करने लगे और क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल होने लगे। साथ ही, आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वह गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ गुप्त बैठक भी करते थे। कहा जाता है कि पंडित कांशीराम और उनके साथियों ने अपने कार्य के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मोगा का सरकारी कोषागार लूटने का प्रयत्न भी किया था। इसी सिलसिले में कांशीराम और उनके साथी पकड़े गए। अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 27 मार्च 1915 को लाहौर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई।

विकास के राजमार्ग पर भारत, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में सात गुना की वृद्धि

देश के सुदूर क्षेत्रों तक सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में प्रतिबद्ध केंद्र सरकार अभूतपूर्व गति के साथ राजमार्गों का निरंतर विस्तार कर रही है। यानि भारत विकास के राजमार्ग पर चल रहा है और आजादी से अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 7 गुना की वृद्धि हुई है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 1950-51 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 19,811 किलोमीटर थी जो 2021-22 में बढ़कर 1,40,995 हो गई। वहीं 2013-14 में 4,260 किलोमीटर की तुलना में 2021-22 में 13,327 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई 2021-22 में इतनी हो गई है कि वह पूरे पृथ्वी के चारों ओर 3.5 बार चक्कर लगा सकता है।

विकास के राजमार्ग

आजादी के बाद से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में सात गुना वृद्धि

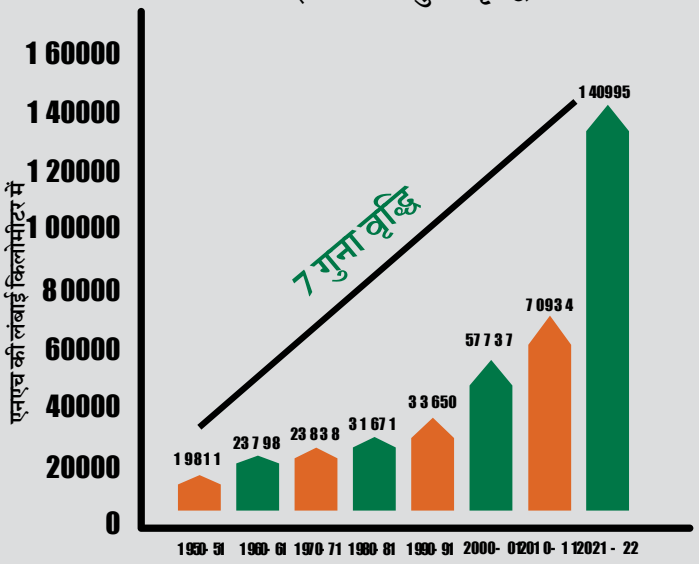

वर्ष 2021-22 का डेटा 31 दिसंबर, 2021 तक का है।

19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़े हेमू कालाणी

जन्म : 23 मार्च 1923, मृत्यु : 21 जनवरी 1943

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश की खातिर बहुत कम उम्र में प्राण न्यौछावर करने वालों में महान क्रांतिकारी हेमू कालाणी भी एक थे। मात्र 19 वर्ष की आयु में इन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी। हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध के सक्खर (अब पाकिस्तान) में हुआ था। उनके पिता का नाम पेसूमल कालाणी और माता का नाम जेठी बाई था। हेमू देशभक्ति की बातें और महान क्रांतिकारियों की कहानी सुनते हुए बड़े हुए। वह बचपन से ही बहुत निर्भीक और साहसी थे। स्कूल जाने के साथ ही वह क्रांतिकारी गतिविधियों में भी सक्रिय हो गए। जब वह आठ साल के थे, तब उनके जन्मदिन पर ही भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। इस घटना का हेमू के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बाद के दिनों में हेमू की एक पहचान यह भी रही कि उन्हें 'सिंध का भगत सिंह' कहा जाने लगा। वह युवा साथियों के साथ गली-मोहल्ले में प्रभात फेरियां करते, आजादी के गीत गाते और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रतिबंधित साहित्य वितरित करते। सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो 19 वर्ष का यह युवक 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' नारे के साथ इस आंदोलन में कूद पड़ा। उन्होंने अपने साथियों के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया। इस आंदोलन के दौरान हेमू कालाणी को पता चला कि बलूचिस्तान में चल रहे उग्र आंदोलन को कुचलने के लिए हथियारों से भरी अंग्रेजों की ट्रेन सिंध के रोहिणी स्टेशन से गुजरेगी। ऐसे में उन्होंने ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए एक योजना बनाई ताकि हथियारों से भरी ट्रेन को लूटा जा सके। इस प्रयास के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। बाद में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 1943 को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि जब हेमू कालाणी को फांसी दी जा रही थी तब उन्होंने 'इंकलाब-जिंदाबाद' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए खुद अपने हाथों से फंदा गले में डाला, मानो फूलों की माला पहन रहे हों। आजादी के बाद 21 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद परिसर में हेमू कालाणी की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया है। साहस, निर्भीकता और देशभक्ति के मामले में उनकी शहादत किसी अन्य शहीद से कम नहीं है। हेमू कालाणी के वीरतापूर्ण कार्य और शहीदों के पदचिन्हों पर चलने की उनकी इच्छा वास्तव में अद्वितीय थी।

चारुचंद्र बोस जिन्हें अपने प्राणों से अधिक प्यारी थी स्वतंत्रता

जन्म : 26 फरवरी 1890, मृत्यु : 19 मार्च 1909

भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन में अपना योग दान देने वाले क्रांतिवीर चारुचंद्र बोस का जन्म 26 फरवरी 1890 को खुलना में हुआ था जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। उनके पिता का नाम केशवचंद्र बोस था। उनके परिवार में देशभक्ति का माहौल था जिनका चारुचंद्र बोस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। वह बाल्यकाल से ही बहादुर और निर्भीक थे। वह दिव्यांग थे और उनके हाथ में अंगुलियां नहीं थी। इसलिए वह दाहिने हाथ में पिस्तौल बांधकर बांये हाथ की अंगुली से ट्रिगर दबाकर पिस्तौल चलाने का अभ्यास करते। सामान्य कद-काठी के चारुचंद बोस देशभक्ति की भावना और जज्बे से ओतप्रोत थे। उन्हें देश की स्वतंत्रता अपने प्राण से भी अधिक प्यारी थी। उन्होंने कोलकाता और हावड़ा में विभिन्न प्रेस और समाचार पत्रों में भी काम किया। क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वह युगांतर संगठन से जुड़ गए। वह अनुशीलन समिति से भी जुड़े रहे। इसी दौरान, आशु बिस्वास नाम का एक सरकारी वकील चारुचंद्र बोस की आंखों में खटकने लगा जो देशभक्त क्रांतिकारियों को हमेशा सजा दिलाने की ताक में लगा रहता था। ऐसे में उन्होंने मन ही मन उस वकील को सबक सिखाने की ठान ली और इसके लिए योजना बनाने लगे। चारुचंद्र बोस, उस वकील पर नजर रखने लगे। एक दिन मौका पाकर उन्होंने फरवरी 1909 को अलीपुर बम मामले में सरकारी वकील आशु बिस्वास की गोली मार कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। अदालत में सुनवाई के समय चारुचंद्र ने कहा कि आशु विश्वास एक देशद्रोही था। मैंने उसे मारने का निश्चय कर लिया था। माना जाता है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्होंने बचने का कोई प्रयास नहीं किया। अपने बचाव के लिए किसी वकील को रखने से भी इंकार कर दिया। अदालत ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुना दी। 19 मार्च, 1909 को अलीपुर केंद्रीय कारागार में उन्हें फांसी की सजा दी गई। कहा जाता है कि फांसी दिए जाने के समय उन्होंने विजयी भाव से स्वयं अपने गले में फंदा डाल लिया। इस दौरान उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी बल्कि मुस्कान तैर रही थी। ●

PMO India

भारत की पहचान हो, भारत की परम्पराएँ हों, या भारत की प्रेरणाएं हों, कर्नाटका के बिना हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते।

रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO I...

हमारी defence industry पर सरकार और समाज का भरोसा इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, कि पिछले साल Indian vendors से procurement के लिए जो हिस्सा 68% किया गया था, 'अमृत काल' से प्रेरित हुए वह हिस्सा आगामी वर्ष के लिए सीधे-सीधे 75% कर दिया गया है: रक्षा मंत्री

Amit Shah

मोदी जी ने गरीबी को नजदीकी से देखा है इसलिए उनकी नीतियों में गरीब कल्याण का विज़न है।

मोदी सरकार में एक क्रोनोलॉजी के तहत नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

2014 से पहले समस्याओं के समाधान के लिए टुकड़ों-टुकड़ों में काम करने का विज़न था। मोदी जी ने समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान का विज़न देश के सामने रखा।

Nitin Gadkari

Representing the true sense of Vasudhaiva Kutumbakam, India always stands for humanitarian values irrespective of the border.

Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji has shown great gestures by exchanging words with rescue and relief personnel who participated in #OperationDost

Narendra Singh Tomar

खेती हो, इंडस्ट्री हो, पर्यटन हो, बेहतर शिक्षा हो या बेहतर स्वास्थ्य हो... यह सब अच्छी कनेक्टिविटी से और सशक्त होते हैं।

इसलिए बीते वर्षों से हम कर्नाटक की कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं।

इस समय कर्नाटक में रेलवे के 45 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।

Bhupender Yadav

2014 तक ESIC के बेड की संख्या 18933 थी और हॉस्पिटल की संख्या 151। पीएम श्री @narendramodi जी द्वारा जब ESIC 2.0 को शुरू किया गया 8 वर्षों में बेड की संख्या 20211 की गई और हॉस्पिटल की संख्या 160 कर दी गई। आने वाले समय में बेड की संख्या 28116 और हॉस्पिटल्स की संख्या 241 हो जाएगी।

वह दिन दूर नहीं जब देशवासी मेड इन इंडिया विमान में घूमेंगे : मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा-आने वाले वर्षों में विमानन क्षेत्र में होगी हजारों युवाओं की जरूरत

दुनिया में बज रहा भारत के उड़यन क्षेत्र का डंका

2014 से पहले जितने हवाईअड्डे थे बीते नौ साल में इतने ही नए बन गए

खरगे सिर्फ नाम के अध्यक्ष, दुनिया जानती है रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है

3,600 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया पीएम मोदी ने शिवमोगा में

2,500 करोड़ लागत वाली जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया शिवमोगा-बेलगावी में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और सहकारिता पर बजट बाद के दूसरे वेबिनार को संबोधित किया

किसानों के लिए निर्यात की राह हुई आसान

संबोधन

1.25 **25** **03**

बजट कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पर केंद्रित

कृषि क्षेत्र लंबे समय तक संकट में रहा

'श्री अन्न' से छोटे किसानों को लाभ होगा

कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को खत्म करना होगा

घर-घर तक पहुंच रही डिजिटल इंडिया की शक्ति

मन की बात : कई देश यूपीआई की तरफ आकर्षित, ई-संजीवनी बना जीवन रक्षक

आर.एन.आई
DELHIN/2020/78812
16-31 मार्च, 2023

न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर- DL (S)-1/3550/2020-22 डब्ल्यूपीपी संख्या- U (S)-98/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110001 on 13-17 advance Fortnightly (प्रकाशन तिथि-2 मार्च 2023, कुल पृष्ठ-52)

अमृत सरोवर
आजादी के अमृत महोत्सव की अनोखी पहलः एक लाख अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य, करीब 62 हजार पर काम शुरू, 34 हजार का निर्माण हुआ पूरा।

विश्व जल दिवस

22 मार्च

भारत के ऋषि-मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति, पर्यावरण और पानी को लेकर संयमित, संतुलित और संवेदनशील व्यवस्था का सृजन किया था। हमारे यहां कहा गया है- 'मा आपो हिंसी।' अर्थात्, हम जल को नष्ट न करें, उसका संरक्षण करें। यह भावना हजारों वर्षों से हमारे अध्यात्म और धर्म का हिस्सा है। यह हमारे समाज की संस्कृति, सामाजिक चिंतन का केंद्र है। इसलिए, हम जल को देव की संज्ञा देते हैं, नदियों को मां मानते हैं। जब कोई समाज प्रकृति से ऐसे भावनात्मक संबंध जोड़ लेता है तो विश्व जिसे सतत विकास कहता है, वह बन जाती है उसकी सहज जीवनशैली...

जल-जन अभियान एक ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पानी की कमी को पूरे विश्व में भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। 21वीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हमारी धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित हैं। इतनी बड़ी आबादी के कारण वॉटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए आजादी के अमृतकाल में आज देश 'जल को कल' के रूप में देख रहा है। जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा। इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे। आज जब भविष्य की चुनौतियों के समाधान खोज रहे हैं तो हमें अतीत की उस चेतना को पुनर्जागृत करना होगा।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधान संपादकः
राजेश मल्होत्रा, प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रकः
मनीष देसाई, महानिदेशक
केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित

मुद्रणः इनफिनिटी एडवर्टाइजिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड,
एफबीडी वन कॉर्पोरेट पार्क, 10वीं मंजिल, नई दिल्ली-
फरीदाबाद बॉर्डर, एनएच-1, फरीदाबाद-121003